twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DLHIN/25/A2321

DD

दिव्य दिल्ली

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

divyadelhi.com | मंगलवार, 02 सितम्बर, 2025 | वर्ष: 01, अंक: 05, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- 09/- दिव्य दिल्ली (इंग्लिस पेपर सहित)

यूक्रेन में शांति का रास्ता खोजना मानवता की पुकार: पीएम मोदी

दोनों नेताओं ने आर्थिक, ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की

नई दिल्ली/तियानजिन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और भारत-रूस साझेदारी की मजबूती की पुष्टि की। बैठक में मोदी ने पुतिन के समक्ष यूक्रेन संघर्ष को भी जल्द समाप्त करने की मांग उठाई। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में संघर्ष के समाधान के लिए हाल में की गई पहलों के प्रति अपना समर्थन दोहराया और संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने तथा एक स्थायी शांति समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया। मोदी और पुतिन ने दोनों देशों के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया कि वह इस वर्ष के अंत में 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए

पुतिन के साथ वार्ता में मोदी बोले- यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए

पीएम मोदी ने आगे कहा, आपसे मिलना एक यादगार अनुभव होता है, ऐसा मैं हमेशा महसूस करता हूं। हमें कई विषयों पर जानकारी साझा करने का मौका मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहते हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें होती रहती हैं। 140 करोड़ भारतीय आपके लिए इस साल दिसंबर में होने वाले हमारे 23वें शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह हमारे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है।

एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की अनौपचारिक वार्ता ।

जम्मू: बाढ़ पीड़ितों से मिले गृहमंत्री शाह

जम्मू

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि वह जिले के सबसे अधिक प्रभावित गांव मंगुचक्क भी जाएंगे। शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने बिक्रम चौक के पास तवी पुल पर रुककर नदी किनारे हुए नुकसान का जायजा लिया। शाह रविवार रात जम्मू पहुंचे थे ताकि बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा कर सकें। वे आज बाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। इसके अलावा, शाह राजभवन में दो अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता करेंगे- एक बैठक बाढ़ राहत कार्यों पर और दूसरी बैठक बाढ़ से सीमा सुरक्षा में आई

बाधाओं को लेकर होगी। 14 अगस्त से अब तक किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण 130 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 33 लोग लापता हैं। 26 और 27 अगस्त को हुई रिकॉर्ड बारिश से जम्मू और अन्य मैदानी इलाकों में भारी बाढ़ आई, जिससे बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। मृतकों में 34 श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। यह पिछले तीन महीनों में जम्मू का शाह का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 29 मई को यहां आए थे, जब भारतीय सेना ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले (जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी) के जवाब में सीमा पार आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे।

एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम ला रहे, मोदीजी मुंह नहीं दिखा सकेंगे: राहुल

पटना

भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन (आईएनडीआईए) की वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार को पटना में समापन हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचे।

इस मौके पर राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में हमसे चुनाव चोरी किया गया था। तकरीबन एक करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े जाते हैं। जितना हमें लोकसभा में मिला, उतना विधानसभा में गया। नए सारे वोट भाजपा के खाते में

चले गए। क्योंकि, चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोट चोरी की। हमने साफ दिखाया कि एक क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। हमने डाटा के साथ दिखाया। चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट नहीं देती। सीसीटीवी नहीं दिखाती। चार महीने, 16-17 घंटे काम कर हमने देश के सामने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। यह आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड लेकर अडाणी-अंबानी को दे देंगे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाली शक्ति संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन्हें संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। हमने बिहार की यात्रा की। बिहार के सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे-छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, गद्दी छोड़। आपने एटम बम का नाम सुना है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पूरे देश को आपकी सच्चाई पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा सकेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संबोधित करते हुए कहा कि इस 15 दिन की यात्रा पूरे देश में चर्चा चली। भाजपा ने इसमें रुकावट डालने की पूरी कोशिश की। गठबंधन के लोग राहुल जी या तेजस्वी जी नहीं डरे। वोट चोरी करने वाले पैसा चोरी करने की भी आदत रखते हैं।

सोना पहली बार 1.05 लाख रुपये के पार, चांदी में भी रिकॉर्ड उछाल

नई दिल्ली : देश में सोने और चांदी की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड रेट ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए है। एक सितंबर को सोना और चांदी अपने आलटाइम हाई पर पहुंच गए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को सोना 2,404 रुपए बढ़कर 1,04,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,02,388 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 5,678 रुपए बढ़कर 1,23,250 रुपए प्रति किलो हो गई है। सोमवार को सोना-चांदी की कीमतों में तेजी आने की वजह अमेरिकी डॉलर में कमजोरी, सितंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती उम्मीदें और ट्रंप टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताएं रही हैं।

हिमाचल: रेड अलर्ट के बीच आसमान से बरसी आफत, भूस्खलन से चार की मौत

शिमला

हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच रविवार से जारी जोरदार बारिश ने तबाही मचाई है। जगह-जगह भूस्खलन से व्यापक नुकसान हुआ है। शिमला की जुन्गा तहसील में पटवार सर्कल डबलू के उप मोहाल जोत में एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया। हादसे में पिता और पुत्री की मौत हो गई है। मृतक की पहचान वीरेंद्र कुमार (35), पुत्र जय सिंह निवासी पटवार सर्कल डबलू के उप मोहाल जोत के रूप में हुई है। हादसे में उसकी 10 वर्षीय बेटी की भी मौत हो गई है। इसके साथ ही मवेशियों की भी मौत हो गई। घटना में मृतक की पत्नी बाल-बाल बच गई, क्योंकि वह

उस समय घर के बाहर थीं।

जुब्बल-कोटखाई में दो लोगों की मौत

उधर, कोटखाई में भारी बारिश की वजह से सुबह खनेटी के चोल गांव में एक मकान भूस्खलन के कारण ढह गया। भूस्खलन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला कलावती पत्नी बालम सिंह की मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं जुब्बल के भौली गांव में आशा देवी पत्नी स्वर्गीय अमर सिंह का मकान भूस्खलन से ढह गया। मलबे में दबने से एक बच्ची कनिष्का की मौत हो गई। प्रभावित परिवार को 30 हजार की फौरी राहत प्रदान की गई है। तहसीलदार जुब्बल और हलका पटवारी मौके पर मौजूद हैं, प्रभावित परिवार को निकटवर्ती सामुदायिक केंद्र में स्थानांतरित किया गया है।

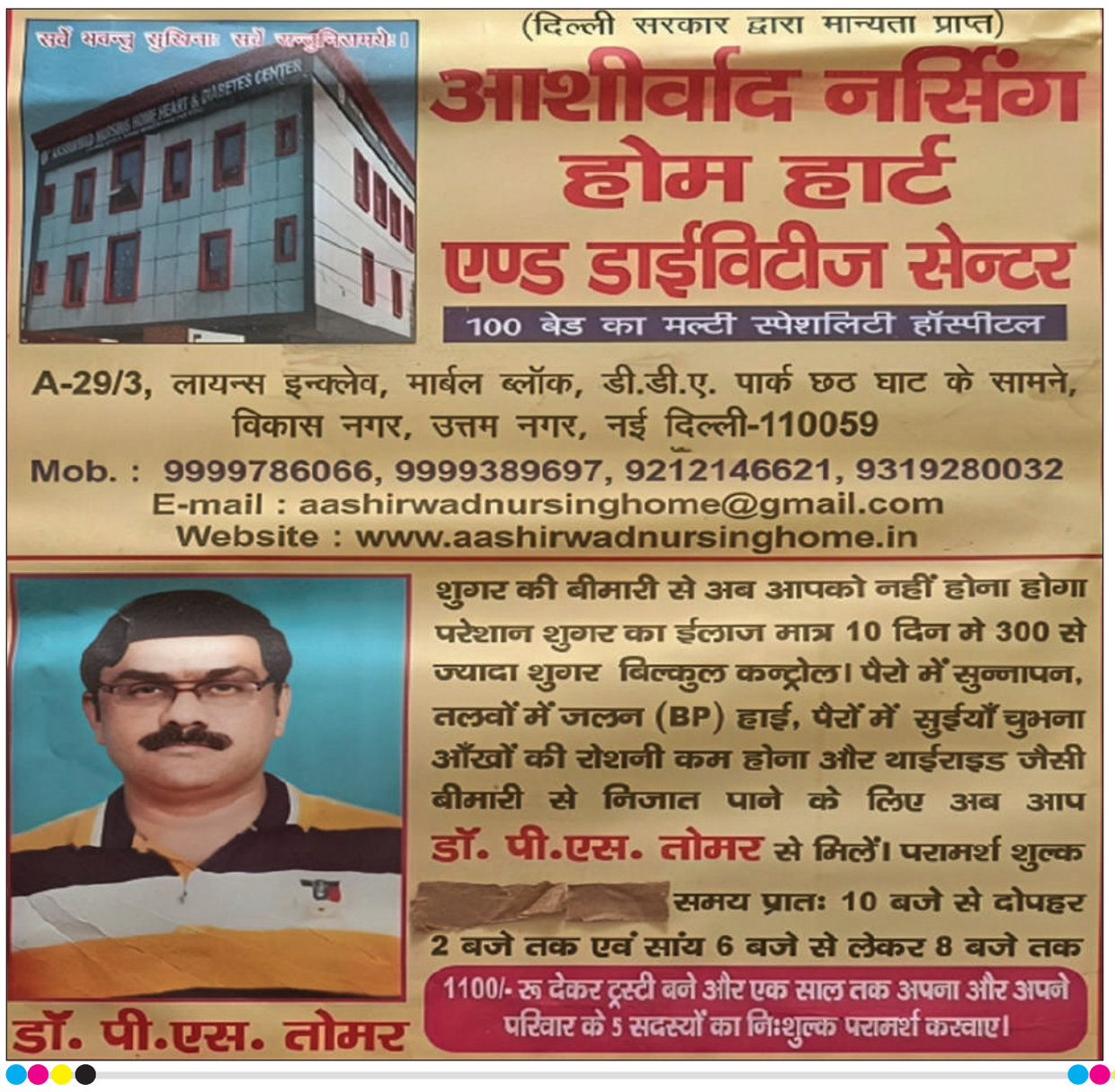

आतंकवाद पर दोहरे मानदंड स्वीकार्य नहीं: पीएम

भारत ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को नकारा, सहयोग का आह्वान

नई दिल्ली
आतंकवाद के खिलाफ भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में सोमवार को टियांजिन (चीन) में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सालाना शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरापन स्वीकार्य नहीं है। इस मंच पर पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ भी मौजूद थे और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर पाकिस्तान की भूमिका जगजाहिर है जबकि चीन भी वैश्विक मंचों पर कई बार इस मुद्दे पर अपने मित्र देश पाकिस्तान को कवर देता रहता है।

घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना की गई

बहरहाल, एससीओ सम्मेलन के बाद जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें हर तरह के आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना की गई है। एससीओ ने भी कहा है कि आतंकवाद पर दोहरा व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। इसे भारतीय रुक के महत्वपूर्ण समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए वैश्विक समुदाय से एकजुट होकर इस चुनौती का मुकाबला करने का आह्वान किया। इआतंकवाद को मानवता के लिए साझा खतरा बताते हुए उन्होंने किसी भी रूप में आतंकवाद के समर्थन को अस्वीकार्य करार दिया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए चुनौती है। कोई भी देश, समाज या नागरिक इससे सुरक्षित नहीं है। हमें स्पष्ट रूप से कहना होगा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड स्वीकार्य नहीं होंगे।

पीएम ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए इसे मानवता के खिलाफ खुली चुनौती बताया और इस दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़े होने वाले मित्र देशों का आभार जताया।

अल-कायदा पर कार्रवाई की मांग

पीएम मोदी ने भारत की एससीओ नीति को तीन स्तंभों सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने एससीओ-रैट्स के तहत अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व किया और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ आवाज उठाई।

भारत ने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया: मोदी

प्रधानमंत्री ने अवसर को सहयोग और सुधार की संभावना बताया। उन्होंने जन संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव दिया कि एससीओ के अंतर्गत एक सभ्यतागत संवाद मंच बनाया जाए, जिससे प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा किया जा सके। भारत का विकास मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 'सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण' के मूलमंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भारत ने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। भारत लगातार व्यापक सुधारों पर काम कर रहा है।

'कनेक्टिविटी के प्रयासों में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी'

कनेक्टिविटी पर भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए पीएम ने चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रयासों का उल्लेख किया, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से संपर्क बढ़ाएगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कनेक्टिविटी के प्रयासों में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी है।

ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को कैद रखना अन्याय

पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधार की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पुराने ढांचों में कैद रखना अन्याय है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर इसके सुधार का आह्वान किया। एससीओ नेताओं की बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में भी आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। इसमें कहा गया कि संगठन के सदस्य देश आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और आतंकी समूहों का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है।

'मानवता के हित में आतंकवाद का हर रंग का विरोध करना होगा'

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए हैं और कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह घटना केवल भारत की आत्मा पर आघात नहीं थी बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और हर व्यक्ति को चुनौती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन स्वीकार्य हो सकता है? उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद पर किसी भी प्रकार के दोहरे मानदंड स्वीकार्य नहीं होंगे। मानवता के हित में सभी को एक स्वर में आतंकवाद का हर रूप और हर रंग में विरोध करना होगा। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्य इस दिशा में आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की अस्सीवीं वर्षगांठ पर सभी सदस्य देश मिलकर सुधार का आह्वान कर सकते हैं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को पुराने ढांचों में कैद रखना आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मत है कि मजबूत संपर्क से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ भारत चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसे उपक्रमों पर काम कर रहा है, जिससे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ सके।

टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक (सीजीए) का पदभार संभाला

नई दिल्ली
भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) की 1991 बैच की अधिकारी टीसीए कल्याणी ने सोमवार को लेखा महानियंत्रक (सीजीए) का पदभार संभाल लिया है। वह इस पद पर आसीन होने वाली 29वीं अधिकारी हैं। उन्?होंने रक्षा, दूरसंचार, उर्वरक, वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सूचना एवं प्रसारण, और गृह मंत्रालय सहित प्रमुख मंत्रालयों में कार्य किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक कल्याणी ने प्रौद्योगिकी को अपनाकर सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता को निरंतर बढ़ावा दिया है। मुख्य लेखा नियंत्रक (सीजीए) का पदभार ग्रहण करने से पहले कल्याणी गृह मंत्रालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआर. सीसीए) के रूप में कार्यरत थीं, जहां उन्होंने भारत सरकार के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक के बजट और लेखा-जोखा का निरीक्षण किया।

'एजुकेट गर्ल्स' को मिलेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

मनीला: लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाली भारतीय संस्था 'एजुकेट गर्ल्स' को वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में शामिल किया गया है। एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संस्था बनकर इसने इतिहास रच दिया है। यह संस्था दूरदराज के गांवों में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास करती है। साथ ही, उन्हें निरक्षरता के बंधन से मुक्त करने और अपनी पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करने के लिए कौशल, साहस और क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से भी काम करती है। 'एजुकेट गर्ल्स' पहली भारतीय संस्था है, जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। दो अन्य विजेताओं में मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के विलानुएवा को भी चुना गया है। भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण इस उपलब्धि पर 'एजुकेट गर्ल्स' की संस्थापक सफीना हुसैन कहती हैं, "यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।

दिल्ली में बाढ़ का खतरा! हरियाणा में हथनीकुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोले

यमुनानगर/नई दिल्ली
पहाड़ों और यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बरसात के कारण यमुना नदी उफान पर आ गई है। हथनी कुंड बैराज पर यमुना नदी में 2 लाख 71 क्यूसेक पानी चल रहा। यमुना की सहायक नदी सोम नदी में भी पांच हजार क्यूसेक जल बहाव चल रहा है। ये पानी दिल्ली में भारी तबाही मचाएगा। ये बहाव इस मानसून का सर्वाधिक है। सिंचाई विभाग के एसई आरएस मित्तल का कहना है कि अभी और यमुना में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज पर 2 लाख 71 क्यूसेक पानी चल रहा है। भारी बरसात चल रही है। यमुना नदी का यह पानी 48 से 60 घंटे में दिल्ली में पहुंच जाएगा यदि पानी का बहाव और तेज होता है तो यह 24 घंटे में दिल्ली में प्रवेश कर जाएगा। हथनी कुंड बैराज से निकलने वाली यूपी की पूर्वी नहर व हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर की जलापूर्ति बंद कर दी गई। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बैराज के यमुना नदी के सभी 18 गेट खोल दिए गए। 15 गेट हरियाणा और तीन गेट उत्तर प्रदेश में है।

एसआईआर: चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनावई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई मतदाता सूची के मसौदे पर आपत्तियाँ दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की काफी कमी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास की इस कमी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

दो न्यायाधीशों की पीठ ने की सुनवाई

बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ मसौदा सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि बिहार के लोगों को विशेष गहन पुनरीक्षण से कोई समस्या नहीं है। केवल याचिकाकर्ता ही इसमें नाराज हैं।

चुनाव आयोग ने पीठ को सूचित करते हुए कहा कि उसे प्राप्त अधिकांश आवेदन मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग करते हैं, और नाम शामिल करने के अनुरोधों की संख्या बहुत कम है।

पारदर्शिता का अभाव

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का बेहद अभाव है। वहीं, इस पर चुनाव आयोग पीठ को बताया कि बाधा डालने की मानसिकता इसके लिए ज़िम्मेदार है।

सरकारी टीचर्स को नौकरी में रहने के लिए टीईटी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला सुनाया। हालांकि, बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं।

5 साल से ज्यादा सर्विस वालों के लिए कंपलसरी

बेंच के निर्देश के अनुसार, ऐसे टीचर्स जिनकी सर्विस में 5 साल से ज्यादा का समय बाकी है, उन्हें सर्विस में बने रहने के लिए ळएळ क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा न करने पर उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा।

माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशंस के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसला

कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशंस पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र मे टीचिंग के लिए टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

क्या है टीईटी एग्जाम

टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के लिए योग्य है या नहीं।

यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी। आरटीई एक्ट, 2009 की धारा 23(1) के अनुसार, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटीई, द्वारा निर्धारित की जाएगी। 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया।

शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टीईटी क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया। जिसे आगे चलकर 4 साल और बढ़ाया भी गया। नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा।

धर्म के काम से मंत्री-नेताओं को दूर रखें: नितिन गडकरी

जहां घुसते हैं, आग लगाते हैं; धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक

नागपुर
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से अपील की कि वे धर्म-काज से मंत्री-नेताओं को दूर रखें। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। गडकरी नागपुर में महानुभाव पंथ के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ जहां घुसते हैं, आग लगाए बिना नहीं रहते। सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो हानि ही होगी। गडकरी ने कहा कि धर्म कार्य, समाज कार्य और राजनीति कार्य अलग-अलग हैं। धर्म व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। कुछ राजनीतिज्ञ इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे विकास और रोजगार का विषय दोयम दर्जे का हो जाता है।

गडकरी बोले-चक्रधर स्वामी की शिक्षाएं सभी लिए प्रेरणा

गडकरी ने कहा कि महानुभाव पंथ के संस्थापक चक्रधर स्वामी की शिक्षाएं सभी के जीवन के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्ति में बदलाव उसके संस्कारों से आता है। चक्रधर स्वामी ने सत्य, अहिंसा, शांति, मानवता और समानता के मूल्य सिखाए। उन्होंने कहा कि जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए।

अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, 800 लोगों की मौत और 2500 घायल

काबुल
अफगानिस्तान में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अफगानिस्तान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई घर मलबे में तब्दील हो गए। इस दौरान 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं, भूकंप के झटकों का असर पाकिस्तान और भारत में भी देखा गया है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, बीती रात अफगानिस्तान समेत दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है।

800 लोगों की मौत

अफगान के नांगरहार जन स्वास्थ्य विभाग ने प्रवक्ता नकीबुल्लाह रहीमी ने भी भूकंप की पुष्टि की है। रहीमी का कहना है कि भूकंप के तेज झटकों से कई घर धराशायी हो गए। अब 800 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है।

कई राज्यों में बाढ़ के मद्देनजर शिवराज ने कृषि क्षेत्र के नुकसान की जानकारी ली

नई दिल्ली
देश के कई राज्यों में हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ ने किसानों की मुसीबतों को बढ़ा दी है। सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की देशभर की स्थिति की समीक्षा के साथ पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। कृषि भवन में सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शिवराज सिंह ने पंजाब के कुछ इलाकों में आई बाढ़ व फसलों पर इसके असर के बारे में भी वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी हासिल की। शिवराज सिंह ने कहा कि पंजाब के किसान भाई-बहन बिल्कुल चिंता नहीं करें, केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा के इस संकट में पूरी तरह प्रभावित किसानों के साथ खड़ी हुई हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि वे आगामी दिनों में पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का रूबरू जायजा लेने के साथ ही मौके पर पीड़ित किसानों से भी मिलेंगे और उन्हें हरसंभव मदद की जाएगी। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डा. देवेश चतुवेर्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने देशभर में कृषि क्षेत्र की स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि खरीफ बुवाई क्षेत्रफल में पिछले वर्ष के मुकाबले आशाजनक वृद्धि हुई है। खाद्यान्न फसलों के साथ ही बागवानी क्षेत्र की प्रगति के बारे में भी केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने जानकारी ली। विशेषकर आलू, प्याज और टमाटर के उत्पादन की स्थिति और कीमतों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों में हो रही बारिश और जलाशयों की स्थिति के बारे में भी बताया, जिसमें कहा गया कि कई राज्यों में इस वर्ष औसत से अधिक बारिश हुई, जो फसलों के लिए लाभदायक स्थिति है। अच्छी बारिश से जलाशय लबालब हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए कि खाद्यान्न फसलों के साथ ही किसानों को बागवानी सहित इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएं, ताकि किसानों को अधिक लाभ हो सकें। भविष्य की मांग के मद्देनजर हमें खेतों में अनाज के साथ अन्य वैकल्पिक उपायों से कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना होगा। बागवानी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग इस दिशा में कारगर उपाय है। उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भी निर्देशित किया।

शाह ने कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना, कहा- गाली भरी भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र को कलंकित करने वाला

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में कांग्रेस और राजद की रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी दिवंगत माताजी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी की निंदा की। शाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने गुजरात के मुख्यमंत्री काल से ही मोदी जी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है, लेकिन अब उन्होंने सारी मयार्दाएं लांघ दी हैं। गुरुवार को अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किए बयान में कहा कि बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है। यह साफ दशार्ता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल-चरित्र में वापस लौट आई है, जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया।

सरकारी शराब की दुकान पर सेल्समैन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला

एजेंसी

नई दिल्ली। उत्तर पश्चिची जिले के भारत नगर इलाके में सरकारी शराब की दुकान पर चार बदमाशों ने सेल्समैन पर चाकू और हॉकी स्टिक से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सेल्समैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर पश्चिची जिले के डीसीपी भीष्म सिंह के अनुसार घटना शाम निमड़ी कॉलोनी कॉम्प्लेक्स स्थित सी-8 सरकारी शराब की दुकान पर हुई। घायल सेल्समैन की पहचान ग्यानपाल सिंह (52) के रूप में हुई है, जो दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम करता है। पुलिस के मुताबिक चार हमलावरों ने अचानक दुकान में घुसकर उस पर चाकुओं और हॉकी स्टिक से हमला बोल दिया। डीसीपी के अनुसार दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों को ग्यानपाल पर वार करते देखा जा सकता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पीड़ित बयान देने की हालत में नहीं है। वहीं, दुकान प्रबंधक समेत कई चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। डीसीपी के अनुसार भारत नगर थाना पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ठगी के मामले में आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक बड़े ऑनलाइन शेयर बाजार घोटाले में मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस घोटाले में नागरिकों को प्री-लॉन्च आईपीओ और शेयर बाजार निवेश के बहाने उनकी मेहनत की कमाई ठग ली गई थी। गिरफ्तार आरोपित की पहचान ऋषि रणधीर सिंह के रूप में हुई है, जो पुणे, महाराष्ट्र के इंदिरा नगर का निवासी है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि यह गिरफ्तारी एक वरिष्ठ नागरिक से 27 लाख की ठगी के बाद हुई है। शिकायतकर्ता को फेसबुक और व्हाट्सएप संदेशों के जरिए लुभाया गया और उन्हें फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद उसे एक फर्जी निवेश टिप्स ग्रुप में जोड़ा गया, जहां उसे आईपीओ फंडिंग और लाभ निकासी के बहाने धीरे-धीरे निवेश करने के लिए उकसाया गया। ठगों ने शिकायतकर्ता से ऑनलाइन के माध्यम से कई बैंक खातों में पैसे जमा करवाए। जब पीड़ित ने अपने निवेश की राशि निकालने की कोशिश की तो ठगों ने धमकियां दी। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। डीसीपी के अनुसार जांच के दौरान, ऋषि रणधीर के नाम से एक खाता सामने आया। जिसमें शिकायतकर्ता के खाते से 8 लाख प्राप्त हुए थे। गहन प्रयासों के बाद, उसकी मौजूदगी दिल्ली के करोल बाग में ट्रेस की गई।

हत्या के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। द्वारका जिले की एंटी-नारकोटिक्स सेल की टीम ने बिंदापुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने मामूली कहासुनी के बाद युवक की छाती में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। पकड़े गए आरोपितों की पहचान भगवती विहार निवासी विपिन उर्फ मुन्ना (19) और राजापुरीनिवासी पवन कुमार उर्फ पंजाबी (23) के रूप में हुई है। द्वारका जिले के डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार घटना 17 अगस्त की है, जब उत्तम नगर स्थित एक अस्पताल से पीसीआर कॉल आई कि एक व्यक्ति कुलदीप को मृत अवस्था में लाया गया है। जिसकी मौत छाती पर चाकू लगने से हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिजन ने बताया कि कुलदीप का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। जिसके बाद आरोपितों ने उसकी छाती में चाकू मार दिया। इस दौरान मृतक के भतीजे को भी चाकू से चोटें आईं। पुलिस ने घायल भतीजे के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। डीसीपी के अनुसार एसीपी ऑपरेशन सेल रामअवतार की देखरेख में एक टीम बनाई गई। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपित लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और मोबाइल फोन बंद कर फरारी काट रहे है। पुलिस ने खुफिया तंत्र और सोशल मीडिया की निगरानी से सबसे पहले आरोपित विपिन उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे आरोपित पवन कुमार उर्फ पंजाबी (23) को पुलिस ने बागपत (उप्र) से पीछा करके दबोचा।

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो आरोपितों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात जफरपुर कला इलाके में मुठभेड़ के बाद कुख्यात कपिल नंदू-गैंग के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की पकड़ में आए आरोपितों की पहचान रोहतक निवासी नवीन उर्फ भांजा (25) और अंबाला छावनी निवासी अनमोल कोहली (26) के रूप में हुई है। दोनों 28 अगस्त को थाना छावला क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में वांछित थे। आरोपितों ने कारोबारी से रंगदारी मांगने के बाद उनके ऊपर फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक बीती देर रात स्पेशल सेल को दोनों आरोपितों के बारे में गुप्त सूचना मिली कि वे जफरपुर कला इलाके में आने वाले हैं। सूचना को पुख्ता कर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी और वे घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से गिरोह की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है और गिरफ्त में आए आरोपितों से आगे की पूछताछ जारी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की कारोबारियों के लिए 1600 करोड़ के जीएसटी रिफंड की घोषणा

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के कारोबारियों की दीपावली को और बेहतर व शानदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के व्यापारियों का वर्ष 2019 से लंबित लगभग 1600 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड दीपावली से पहले अदा करने की घोषणा की। इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने कैंप ऑफिस 'मुख्यमंत्री जनसेवा सदन' में व्यापार एवं कर विभाग (जीएसटी) की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। इसमें जीएसटी आयुक्त नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में दिल्ली के व्यापारियों के हित में यह विशेष निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस लंबित धनराशि के भुगतान की दिशा में पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने इस मामले को

गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यह संपूर्ण रिफंड दीपावली से पहले व्यापारियों को अदा कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि रिफंड निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित जांच प्रक्रिया पर आधारित होगा, जिससे रिफंड आवेदन शीघ्रता से निपट सकेंगे और कारोबारियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बकाया, निर्विवादित और वास्तविक रिफंड आवेदनों का निपटारा संबंधित नियमों के अनुसार जल्द-से-जल्द किया जाए और इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध रिफंड से कारोबारियों को पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, उनकी मुकदमेबाजी की लागत घटेगी और समग्र रूप से दिल्ली की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को मजबूत बनाना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार कारोबारी जगत की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझते हुए, उनके हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए लगातार ठोस व प्रभावी प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में हमारी सरकार ने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया है।

वजीरपुर में दो नाबालिग बच्चों की नहर में डूबने से मौत

एजेंसी

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिले के वजीरपुर क्षेत्र में 29 अगस्त की शाम लापता हुए दो नाबालिग बच्चों, वैभव (11) और यश (12) के शव जे.जे. कॉलोनी के पास एक नहर से बरामद किए गए। दोनों बच्चे जे.जे. कॉलोनी, वजीरपुर के निवासी थे और छठी कक्षा के छात्र थे। पुलिस आशंका जाहिर कर रही है कि बच्चे नहाने के लिए नहर में उतरे और गहरे पानी में डूब गए। मामले की जांच जारी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 30 अगस्त को भारत नगर थाने में दो बच्चों के लापता होने की सूचना एक पीसीआर कॉल के जरिए मिली। कॉल में बताया गया कि ए-17, जे.जे. कॉलोनी, वजीरपुर निवासी वैभव और एन-17बी/409, जे.जे. कॉलोनी निवासी यश दोनों दोस्त थे और 29 अगस्त की शाम 6 बजे से लापता है। वैभव की मां शांति देवी (50) के बयान के आधार पर थाना भारत नगर में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस दौरान सूचना मिली कि जे.जे. कॉलोनी के पास नहर में दो शव तैरते दिखे है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। परिवार वालों ने शवों की पहचान वैभव और यश के रूप में की। क्राइम और फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। नहर के किनारे दोनों बच्चों के कपड़े और जूते व्यवस्थित तरीके से रखे मिले। जिससे आशंका जाहिर की जा रही कि वे तैरने या नहाने के लिए नहर में उतरे होंगे। नहर का पानी उस स्थान पर 15-20 फीट गहरा है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आगे की जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत के सटीक कारणों का पता चलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मलयाली समाज संग हर्षोल्लास से मनाया ओणम उत्सव

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'मुख्यमंत्री सेवा सदन में' मलयाली समाज के साथ ओणम उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने न केवल पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियों में सहभाग किया, बल्कि स्वयं अतिथियों को ओणम के पारंपरिक व्यंजन परोसकर उन्हें घर जैसा अपनापन दिया।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित मलयाली समाज और अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि आप सबको मेरी ओर से ओणम के इस पावन पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यह मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि आप सब आज मेरे घर, इस 'जन सेवा सदन' में आए और इस त्योहार का शुभारंभ यहीं से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओणम केवल फसल और समृद्धि का पर्व नहीं, बल्कि यह भाईचारे, एकता और साझा खुशियों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 10 लाख मलयाली परिवार रहते हैं, जिन्होंने न केवल अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है बल्कि

दिल्ली को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध भी किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज ओणम केवल केरल राज्य का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अब पूरे भारत और विश्वभर में फैले मलयाली समाज के कारण वैश्विक पर्व बन गया है। यह समाज अपनी मेहनत, ईमानदारी, सहयोग भाव और राष्ट्रप्रेम के लिए पूरे देश में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर समुदाय को बराबर सम्मान देती है। मलयाली समाज ने दिल्ली को अपनी विविधता, मेहनत और सेवा भाव से और समृद्ध बनाया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आइए, हम सब मिलकर इस पर्व से प्रेरणा लें और दिल्ली को भी ऐसा ही परिवार बनाएं, जहां हर धर्म, हर समाज, हर परंपरा को बराबरी का सम्मान मिले और सब मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने सभी मलयाली परिवारों और नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले दस दिनों तक दिल्ली इस पर्व की उमंग और उल्लास में डूबी रहेगी।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के चीन दौरे पर उठाए सवाल

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा की कांग्रेस पार्टी ने आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस दौरे का मूल्यांकन राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

जयराम रमेश ने अपने एक्स पिस्ट में कहा कि जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी आक्रामकता के दौरान 20 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके बावजूद 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। सीमा पर यथास्थिति बहाल करने में विफल रहने के बावजूद सरकार चीन के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिससे बीजिंग की आक्रामकता को अप्रत्यक्ष वैधता मिल रही है। जयराम रमेश ने इसी साल 4 जुलाई को उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी पर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस गंभीर चुनौती पर ठोस कदम उठाने के बजाय चुप्पी साध ली और अब चीन को राजकीय दौरों से पुरस्कृत कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा यारलुंग त्सांगपो नदी पर विशाल जलविद्युत परियोजना की घोषणा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गंभीर खतरा है लेकिन केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

जयराम रमेश ने कहा कि चीन

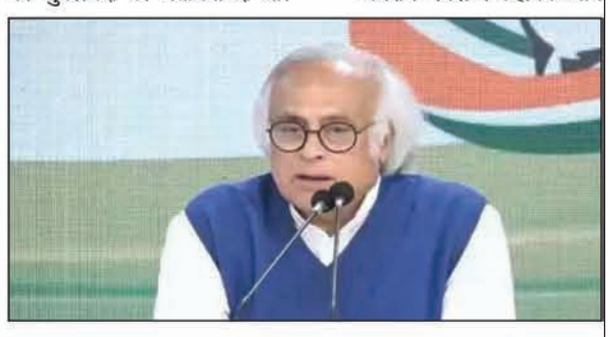

से आयात की अनियंत्रित डंपिंग से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अन्य देशों की तरह सख्त प्रतिबंध लगाने के बजाय भारत ने चीनी आयात को खुली छूट दे रखी है।

भारत की एजुकेट गर्ल्स संस्था रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड 2025 से सम्मानित

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख सामाजिक संस्था एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा की गई है। यह सम्मान 7 नवंबर 2025 को फिलीपींस की राजधानी मनीला के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में आयोजित 67वीं रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड सेरेमनी में औपचारिक रूप से दिया जाएगा। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन ने कहा ने बताया कि यह पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को बालिकाओं और युवतियों की शिक्षा के समाज की अतार्किक सांस्कृतिक धारणाओं को चुनौती देने, उन्हें निरक्षरता से मुक्त करने और उन्हें कौशल, हिम्मत और आत्मनिर्भरता देने के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि एजुकेट गर्ल्स संस्था अब उस गौरवशाली पंक्ति का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें सत्यजीत रे, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, किरण बेदी, विनोबा भावे, दलाई लामा, मदर टेरेसा और ऑस्कर विजेता हयाओ मियाजाकी जैसी विश्वप्रसिद्ध विभूतियां शामिल हैं। सफीना हुसैन ने कहा कि यह उपलब्धि हमारी टीम,

बालिका स्वयंसेवकों, पार्टनर्स, समर्थकों और सबसे बढ़कर उन बच्चियों के नाम है, जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत, शिक्षा को फिर से हासिल किया। आने वाले दस वर्षों में एजुकेट गर्ल्स एक करोड़ से भी ज्यादा शिक्षार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। भारत के इस मॉडल को अब दुनिया के अन्य हिस्सों में भी साझा करने की योजना है, ताकि हर बच्ची को उसका शिक्षा के हक दे सके। हमें पूरा यकीन है कि जब एक लड़की पढ़ती है, तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता, वह अपने साथ पूरे समाज को आगे बढ़ाती है। एजुकेट गर्ल्स की सीईओ गायत्री नायर लोबो ने कहा कि हमारे लिए शिक्षा सिर्फ विकास का साधन नहीं, बल्कि हर लड़की का बुनियादी अधिकार है। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार, कॉरपोरेट, डोनर्स और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो गहरी सामाजिक और संरचनात्मक चुनौतियों को बदला जा सकता है। हम भारत सरकार के प्रयासों और सहयोग के लिए आभारी हैं, जिन्होंने इस मिशन को संभव बनाया। साथ ही, मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फादर फ्लावियानो विलनुएवा को भी हार्दिक बधाई, जिनके काम ने हम सभी को प्रेरित किया है। 2007 में स्थापित एजुकेट गर्ल्स आज तक 30,000 से अधिक गांवों में अपनी पहुंच बना चुकी है। 55,000 से ज्यादा सामुदायिक स्वयंसेवकों के सहयोग से संस्था ने 20 लाख से अधिक बशिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया है और 24 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाया है।

रामलीला प्रभु राम के संदेशों को पहुंचाने का अद्वितीय माध्यम : रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लव-कुश रामलीला कमेटी और श्री लीला कमेटी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में बताया कि आज प्रभु श्रीराम के संदेशों के प्रचार-प्रसार के इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने का सौभाग्य मिला। रामलीला, प्रभु श्रीराम के जीवन मूल्यों और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का अद्वितीय माध्यम है। इस परंपरा को और अधिक सुगमता से आगे बढ़ाने लिए दिल्ली सरकार ने रामलीला समितियों के लिए सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार रामलीला समिति के समक्ष आने वाली हर समस्या का समाधान करेगी, वो चाहे ट्रांसफार्मर जैसी तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति की हो या अन्य व्यवस्थाओं की, सभी का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सबकी यही आकांक्षा है कि दिल्ली में मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित करें, जहां प्रभु श्रीराम के आदर्श साकार हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री धार्मिक लीला कमेटी वर्षों से भव्य रामलीला का आयोजन कर प्रभु श्रीराम के जीवन मूल्यों और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने भक्ति और आस्था से जुड़ी इस पावन परंपरा को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए समिति को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

भारत दुनिया के श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में खड़ा हो रहा है : दत्तात्रेय होसबाले

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने यहां कहा कि भारत करवट ले रहा है और दुनिया के श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में खड़ा हो रहा है। वह राष्ट्र निर्माण में दरभंगा राज के अध्यात्मिक और सांस्कृतिक योगदान पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर 'राज दरभंगा - धर्म संरक्षण से लेकर लोक कल्याण तक' पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

श्री होसबाले ने कहा कि विदेश के इतिहासकारों ने इस मिथ को स्थापित किया कि राजा मौज-मस्ती और विलासिता में डूबा रहता है, लेकिन हमारे देश में राजा को लोक कल्याण के कार्यों के साथ उच्च मानक स्थापित करने वाले के तौर पर देखा गया। उन्होंने कहा कि भारत में राजा को देवता माना गया जो प्रजा के लिए समान भाव के साथ मर्यादा का पालन करते थे। हमारे देश में प्रभु श्रीराम, राजा दशरथ, राजा हरिश्चंद्र, राजा भगीरथ ने लोक कल्याण और मर्यादा के प्रतिमान स्थापित किए। श्री होसबाले ने मिथिला के स्वर्णिम इतिहास और परंपरा पर चर्चा करते हुए कहा कि सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और लोक कल्याण के क्षेत्र में लंबी फेहरिस्त है।

उन्होंने इस अवसर पर दरभंगा राजघराने के कुमार अरिहंत को 18वें जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि दरभंगा के राजा ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन का भी आयोजन किया था और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में भी आगे बढ़कर मदद की थी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कई आधुनिक संस्थानों की स्थापना के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में शुरूआती पांच लाख की राशि दी थी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के लिए एक करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रबंध कराया था। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जब मैं पहली बार 2014-2015 में दरभंगा पहुंचा तो वहां के स्थापत्य, कला और साहित्य से अभिभूत हो गया। उन्होंने मिथिला की धरती और दरभंगा राजघराने को इतिहास की बेमिसाल धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि मिथिला की धरती राजा जनक और माता सीता के साथ गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद की भी साक्षी रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मिथिला की धरती मधुबनी पेंटिंग, ध्रुपद परंपरा को पुष्पित और पल्लवित किया है।

गैंगस्टर हाशिम बाबा का शूटर गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर हाशिम बाबा के खास शूटर असद अमीन (23) को गिरफ्तार किया है। गोकुलपुरी इलाके में एक युवक पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस को असद की तलाश थी। लगातार स्थानीय पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। पुलिस को आरोपित के पास से एक पिस्टल व तीन कारतूस बरामद हुए हैं। असद को हाशिम के बेहद करीबी बताया जा रहा है। इसके खिलाफ दिल्ली और यूपी में कई मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने अपने थाने में अवैध हथियार का एक मामला अलग से दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि गोकुलपुरी में हुई वारदात के बाद से लगातार लोकल पुलिस असद की तलाश कर रही थी। जांच में अपराध शाखा की टीम को शामिल कर लिया गया। टीम ने असद की तलाश शुरू कर दी। इस बीच 26 अगस्त को टीम को खबर मिली कि आरोपी बाराखंभा रोड, नई दिल्ली आने वाला है।

घुमंतू समाज के लिए स्थायी आवास, शिक्षा व रोजगार हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि घुमंतु समाज के प्रत्येक परिवार को स्थायी आवास उपलब्ध कराना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस समाज के हर परिवार को छत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जहां इन परिवारों को बसाया जाएगा, वहीं रोजगार की सुविधाओं और हाट-बाजार की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि आजीविका और जीवन-यापन दोनों सुनिश्चित हों। मुख्यमंत्री ने यह विचार विमुक्त, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम मे व्यक्त किए। दिल्ली सरकार के कला व संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा व रविंद्र इंद्राज सिंह के अलावा अन्य गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों के सम्मान और उनके सशक्तीकरण के लिए इतना व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस आयोजन ने न केवल इन समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर को सामने रखा बल्कि समाज में उनकी पहचान को भी मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने अपने भावनात्मक संबोधन में कहा कि आजादी के 78 वर्षों बाद भी घुमंतु समाज उपेक्षा और संघर्ष की कड़ी परिस्थितियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में इन समुदायों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, किंतु पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी उनकी वास्तविक चिंता नहीं की।

उन्होंने कहा कि आज यह पहली बार है, जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उनके जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संवेदनशीलता और दूरदृष्टि का सम्मान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घुमंतु, विमुक्त और अर्ध-घुमंतु समुदायों के लिए बोर्ड का गठन कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब से उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला है, तभी से प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए थे कि घुमंतु समाज के प्रत्येक परिवार को आवास उपलब्ध कराया जाए। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए विस्तृत योजना तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री ने दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि घुमंतु समाज के प्रत्येक परिवार को स्थायी आवास उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि चाहे वित्तीय चुनौतियां कितनी ही बड़ी क्यों न हों, लेकिन हर परिवार को छत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जहां इन परिवारों को बसाया जाएगा, वहीं रोजगार की सुविधाओं और हाट-बाजार की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि आजीविका और जीवन-यापन दोनों सुनिश्चित हों।

शांति मानवता का सच्चा मार्ग और अहिंसा उसकी सबसे बड़ी ताकत : विजेंद्र गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शांति मानवता का सच्चा मार्ग है और अहिंसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह बात उन्होंने भारत के पहले गुरुग्राम के वर्ल्ड पीस सेंटर में आयोजित 'विश्व शांति, सद्भाव और शांति शिक्षा' पर आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। अहिंसा विश्व भारती द्वारा आचार्य डॉ. लोकेश मुनि के मार्गदर्शन में आयोजित इस संगोष्ठी में भारत और विदेश से आए अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने वैश्विक शांति, सद्भाव और शांति शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका पर विचार-विमर्श किया। विजेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का इतिहास शांति और अहिंसा का इतिहास है। भगवान महावीर ने कहा था 'अहिंसा परम धर्म है', भगवान बुद्ध ने करुणा से एकजुट महाद्वीप का सपना देखा था और महात्मा गांधी ने यह सिद्ध किया कि सत्य और अहिंसा से साम्राज्यवादी शक्तियों को भी परास्त किया जा सकता है।उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पुनर्जीवित किया है। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, जी20 और ब्रिक्स में कहा – 'यह युद्ध का युग नहीं, बल्कि शांति, स्थिरता और सहयोग का समय है।' भारत ने समय रहते दुनिया को यह संदेश दिया कि भविष्य युद्ध में नहीं, बल्कि शांति में है। विजेंद्र गुप्ता ने भारत की 'विश्व गुरु' के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की पहचान शांति और अहिंसा के मूल्यों में गहराई से निहित है, जो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की शिक्षाओं में निहित है। गुप्ता ने वर्ल्ड पीस सेंटर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच होने वाले आगामी सहयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह साझेदारी शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी और 'वसुधैव कुटुंबकम' – पूरी दुनिया एक परिवार है – का संदेश सीमाओं के पार ले जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भागीदारियां यह सिद्ध करती हैं कि मानवता की समस्याओं का समाधान युद्ध से नहीं, बल्कि सहयोग, संवाद और परस्पर सम्मान से होता है। गुप्ता ने कहा कि डॉ. लोकेश ध्यान, योग और शांति शिक्षा के विशेषज्ञ हैं।

संपादकीय

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर कट्टरपंथियों के जुल्म का सिलसिला जारी

बांग्लादेश में यौन हिंसा का एक खतरनाक दौर जारी है। देश में विशेष रूप से हिंदू, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं और बच्चों को शामिल किया जा रहा है, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत महामारी जैसी स्थिति में पहुंच गया है। बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए मानवाधिकार कांग्रेस (एचआरसीबीएम) ने हाल ही मे अपनी एक रिपोर्ट में बेहद शर्मसार करने वाली जानकारी साझा की है।

ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सलीश सेंटर (एएससीई) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की पहली तिमाही के दौरान तीन महीने से भी कम समय में आधिकारिक तौर पर बलात्कार के 342 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में से 87 प्रतिशत में पीड़ित 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ थीं।इनमें से 40 पीड़ित किशोर बारह से लेकर छह वर्ष की आयु के बीच के बच्चे थे, जबकि सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिनमें से अधिकांश पीड़ित किशोर अवस्था शामिल हैं। अधिकार संस्था के अनुसार, ये वैज्ञानिक सिद्धांत तो बस एक छोटे से हिस्से में हैं, और वास्तविक संख्या हजारों में है, जो शैले, भय और राज्य की निष्क्रियता के कारण बनी हुई है।

बांग्लादेश में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के ज्यादातर मामले सामाजिक कलंक, बदले की कार्रवाई के डर और न्याय व्यवस्था में अविश्वास के कारण दर्ज नहीं हो पाए।अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों के मामले में तो यह महिला और भी गहराई में है। मुकदमे में धार्मिक भेदभाव के आरोप परिवार को न्याय से भिन्न मिलते हैं, जिससे अपराध दर्ज नहीं होता और सजा नहीं होती।

एचडीएफसीसीबीएमजारी द्वारा एक बयान में कहा गया है, कई मामलों में, देश भर में महिलाएं और लड़कियों के शव मिले हैं जो सिर तक गायब हैं और उनकी पहचान असंभव हो गई है। इसमें दस्तावेजों के चरित्र का पता चलता है।

यूनुस शासन के तहत बांग्लादेश (बांग्लादेश) में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बारे में, मानवाधिकार संस्था ने कहा कि निराधार आंदोलन और बढ़ते जनाक्रोश के बावजूद, एक प्रमुख हिंदू नेता को आतंकवादी करार दे कर सनातनी चिन्मय कृष्ण दास नवंबर से जेल में बंद हैं। आपको पता रहे कि 5 अगस्त, 2024 को बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद उनके प्रबल विरोधी 'मोहम्मद यूनुस' के नेतृत्व में बंगलादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से बंगलादेश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है।

वहां हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों व अन्य गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। गत वर्ष 4 अगस्त से इस वर्ष जुलाई 2025 के बीच साम्प्रदायिक हिंसा की 2500 घटनाएं हो चुकी हैं तथा इस्लामिक कट्टरवादियों ने एक वर्ष के दौरान कम से कम 79 मंदिरों में तोड़-फोड़ की है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यूनुस सरकार का ध्यान अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की ओर दिलाने के बावजूद हालात ज्यों के त्यों हैं।

बंगलादेश की 'अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस' के अनुसार बंगलादेश की अंतरिम सरकार का वहां की कानून-व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। देश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा की खतरनाक लहर चल रही है।

बंगलादेश के मानवाधिकार संगठन की रिपोर्टों के हवाले से 'अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस' ने बताया है कि 2025 की पहली तिमाही के दौरान वहां आधिकारिक तौर पर बलात्कार के 342 मामले दर्ज किए गए। यहां तक कि बंगलादेश में दिव्यांग लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी वर्ष जून में 7 दिव्यांग लड़कियों से बलात्कार किया गया। अधिकांश मामलों में महिलाओं व लड़कियों के सिर विहीन शव पाए गए हैं। यहां आपको बता दें कि सबसे बुरी बात यह है कि अब बंगलादेश की अदालतों में मामले धार्मिक पूर्वाग्रह आधार पर तय किए जा रहे हैं जिस कारण वास्तविक दोषियों के विरुद्ध केस दर्ज नहीं होते और पीड़ितों को न्याय ही नहीं मिलता। कई अधिकार समूहों के अनुसार बंगलादेश में वर्ष 2024 और मई 2025 के बीच राजनीतिक वर्करों तथा छोटे कारोबारियों व अन्य लोगों सहित भीड़ द्वारा की गई हिंसा में 174 से अधिक लोग मारे गए हैं व 500 से अधिक फैक्टरियां बंद हो जाने से 1 वर्ष में 1.20 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इतना ही नहीं गत मास एक 'झूठे फेसबुक अकाऊंट' से की गई टिप्पणियों के आधार पर 'रंजन' नामक एक निर्दोष हिंदू छात्र की गिरफ्तारी के बाद इस्लामिक कट्टरवादियों द्वारा 'अलदादपुर' गांव में स्थित उसके घर सहित 30 से अधिक हिंदुओं के मकानों पर हमला करके लूट लिया गया।कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को धर्म परिवर्तन करने या देश छोड़ने तथा सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देने के लिए विवश करने के अलावा देश के मंदिरों के प्रबंधकों को पत्र भेज कर उनसे इस्लाम अपनाने या बंगलादेश छोड़ने को भी कह रहे हैं। 'शेख हसीना' की सरकार का तख्ता पलटने के बाद 1 वर्ष के दौरान बंगलादेश की सरकार ने भारत के साथ अपने रिश्ते काफी बिगाड़ लिए हैं। एक ओर हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने भारत और बंगलादेश के संबंधों में तनाव बढ़ाया है तथा दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस की चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।1971 में अपनी स्थापना के बाद से शेख मुजीबुर्रहमान ने बंगलादेश में जो सामाजिक सुधार किए थे, वे सुधार अब इतिहास बन गए हैं और बंगलादेश भी पाकिस्तान की तरह धार्मिक कट्टरवाद की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में अपने ही अतीत और इतिहास को मिटाने पर अमादा है जो वहां बंगलादेश के जन्मदाता 'शेख मुजीबुर्रहमान', 'गुरुदेव रबींद्र नाथ टैगोर' और फिल्मकार 'सत्यजीत रे' जैसी महान हस्तियों के मकानों को नष्ट करने तथा वहां की पाठ्य पुस्तकों से उनका उल्लेख एवं 'शेख मुजीबुर्रहमान' और बंगला मुक्ति संग्राम संबंधी अध्याय निकालने से स्पष्ट है।भारत के पड़ोस में इस तरह का परिवर्तन न तो बंगलादेश के लिए अच्छा है और न ही भारत के लिए।

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट में हिंदुओं, अहमदिया मुसलमानों और आदिवासियों पर हुए हमलों की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अवामी लीग के नेताओं, अल्पसंख्यकों और चटगांव पहाड़ी इलाकों के आदिवासियों के खिलाफ हिंसा को दबाने के प्रयास किए गए।

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा में भी पिछले कुछ सालों से कट्टरपंथी तत्व अड़चन डालते हैं। हिन्दू अल्पसंख्यकों में आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा को लेकर असमंजस और असुरक्षा की भावना बनी है। देखना है कि वहां की सरकार अल्पसंख्यक हिन्दुओं के लिए अपने रूख में सहिष्णुता दशार्ती है या चरमपंथियों के सामने घुटने टेकती है।

शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी: सुविधा से जंजाल तक की यात्रा

डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी। उस समय इसे शिक्षा जगत में बड़े सुधार के रूप में देखा गया। दशकों से यह आरोप लगता रहा कि तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी रहते थे। कई शिक्षक मनचाही जगह सेवा करते थे जबकि अन्य दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में वर्षों तक फंसे रहते थे। इस असमानता ने शिक्षा व्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुँचाया।

ऑनलाइन पॉलिसी ने शुरू में उम्मीद जगाई। कहा गया कि शिक्षक अपनी पसंद और प्राथमिकता ऑनलाइन दर्ज करेंगे और मेरिट के आधार पर तबादला होगा। इससे भेदभाव खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी। परंतु नौ साल बाद यह योजना अब विवादों और असंतोष का दूसरा नाम बन चुकी है।

आश्वासन और हकीकत

हर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले आश्वासन दिया जाता है कि ट्रांसफर होंगे, लेकिन अक्सर यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इस साल भी अप्रैल में घोषणा की गई थी कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ट्रांसफर सत्र शुरू होने से पहले कर दिए जाएंगे। मगर अगस्त बीत गया और शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। जब-जब ऐसी घोषणाएँ अधूरी रह जाती हैं, तो शिक्षकों का मनोबल टूटता है और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

ब्लॉक सिस्टम की पेचीदगी

इस नीति की सबसे बड़ी खामी ब्लॉक सिस्टम है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासनिक सुविधा मिलती है और शिक्षक नजदीकी ब्लॉक में ही स्थानांतरित होते हैं। लेकिन व्यवहार में यह उल्टा साबित हुआ। कई बार एक ही ब्लॉक में किसी विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी होती है, वहीं कुछ विद्यालयों में जरूरत से ज्यादा स्टाफ मौजूद होता है। नीति की जटिलता के कारण समायोजन नहीं हो पाता और विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

एक उदाहरण समझिए–मान लीजिए एक ब्लॉक में गणित के शिक्षक की 15 सीटें हैं लेकिन वहां 20 शिक्षक तैनात हैं, जबकि उसी जिले के दूसरे ब्लॉक में 10 सीटें खाली पड़ी हैं। ब्लॉक सिस्टम के कारण अतिरिक्त शिक्षक चाहकर भी खाली स्कूलों में नहीं भेजे जा सकते। इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होता है।

शिक्षकों का दृष्टिकोण

शिक्षक केवल अपनी सुविधा के लिए तबादले नहीं मांगते। वे चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चले, ताकि उनकी मेहनत सार्थक हो सके। जब वर्षों तक ट्रांसफर लंबित रहते हैं, तो शिक्षक घर-परिवार से दूर रहकर मानसिक तनाव झेलते हैं। कई महिला शिक्षक छोटे बच्चों को छोड़कर दूरदराज स्थानों पर सेवाएँ दे रही हैं। ऐसे हालात में उनका मन पढ़ाई पर कितना केंद्रित रह पाता होगा, यह सोचना मुश्किल नहीं।

दूसरी ओर, कई शिक्षक लंबे समय से एक ही जगह टिके हुए हैं। इससे उन पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। यह भी सच है कि लंबे समय तक एक ही विद्यालय में रहने वाले शिक्षक और प्रधानाध्यापक स्थानीय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं और शिक्षा से ज्यादा निजी हितों में उलझ जाते हैं। इस असंतुलन को खत्म करना बेहद जरूरी है।

शिक्षा पर असर

जब किसी विद्यालय में वर्षों तक विज्ञान या गणित का शिक्षक नहीं होता, तो छात्र पीछे रह जाते हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम गिरते हैं और इसका दोष अक्सर छात्रों या अभिभावकों पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन असली जिम्मेदार प्रणाली है, जो समय पर सही अध्यापक नहीं भेज पाती। शिक्षा का अधिकार कानून (फळए) कहता है कि हर विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी की कमजोरियों ने इस लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया है।

संगठन की भूमिका

हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। संगठन का कहना है कि सरकार को समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव शुरू करनी चाहिए। यदि कोई स्कूल खाली रह जाता है, तो जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को डिप्यूटेशन का अधिकार दिया जाए। यह सुझाव व्यवहारिक है, क्योंकि इससे तत्कालीन संकट टाला जा सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी इच्छाशक्ति दिखाएगी?

कई बार लगता है कि ट्रांसफर पॉलिसी का उपयोग प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। जब चाहा प्रक्रिया रोक दी जाती है और जब चाहा कुछ तबादले चुनिंदा लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। इससे शिक्षकों का विश्वास डगमगाता है।

डिजिटलाइजेशन बनाम जमीनी हकीकत

सरकार ने पॉलिसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालकर इसे ई-गवर्नेंस की सफलता बताया। लेकिन केवल पोर्टल बना देने से समस्या हल नहीं होती। डिजिटल प्लेटफॉर्म तभी सफल होता है जब उसमें समयबद्धता और जवाबदेही हो। यदि हर साल प्रक्रिया अधूरी ही छोड़ दी जाए, तो ऑनलाइन सिस्टम भी महज दिखावा बनकर रह जाता है।

आज हाल यह है कि कई शिक्षक हर साल ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फीस जमा करते हैं, दस्तावेज अपलोड करते हैं, लेकिन अंत में परिणाम कोई ट्रांसफर नहीं निकलता है। ऐसे में उनमें गुस्सा और हताशा स्वाभाविक है।

शिक्षा मंत्री और हकीकत

शिक्षा मंत्री बार-बार कहते हैं कि जल्द ही ट्रांसफर होंगे लेकिन नौकरशाही और नीति की जटिलता के कारण बात आगे नहीं बढ़ती। इस बीच, सत्र बीत जाता है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा में रहता है, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होती।

समाधान क्या है?

ब्लॉक सिस्टम की समीक्षा झ इसे या तो खत्म किया जाए या लचीला बनाया जाए, ताकि शिक्षक जरूरत वाले स्कूलों तक पहुँच सकें।

समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव झ हर साल अप्रैल से पहले प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य किया जाए।

डिप्यूटेशन का अधिकार जिला स्तर पर झ खाली स्कूलों को भरने के लिए अधिकारियों को अधिकार दिया जाए।

पारदर्शिता और जवाबदेही झ यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होता, तो स्पष्ट कारण बताए जाएं।

मानवीय दृष्टिकोण - महिला शिक्षकों, विकलांग शिक्षकों और कठिन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान हों।

शिक्षा की आत्मा

समाज में शिक्षा सबसे पवित्र कार्य है। यदि शिक्षक ही असंतोष में रहेंगे, तो वे विद्यार्थियों तक सकारात्मक ऊर्जा कैसे पहुँचाएंगे? एक निराश और हताश शिक्षक बच्चों को वही भाव देगा जो उसके भीतर है। इसलिए शिक्षक की समस्याओं को केवल ट्रांसफर की मांग मानकर टालना सही नहीं। यह शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने का सवाल है।

सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों को केवल डाटा न माने, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला समझे। शिक्षक का मनोबल तभी ऊँचा होगा जब उसे न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी।

सुधार की जरूरत या असंतोष का अड्डा

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा करके उसमें आवश्यक सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

जब तक इस नीति में पारदर्शिता, समयबद्धता और मानवीय दृष्टिकोण नहीं जुड़ता, तब तक यह केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती फाइलें भर रहेगी, जमीनी हकीकत में नहीं।

शिक्षकों की आवाज अनसुनी करना न सिर्फ उनके साथ अन्याय है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। सरकार को तुरंत कदम उठाकर इस जंजाल को दूर करना चाहिए। तभी शिक्षा का स्तर सुधरेगा और शिक्षक अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा पाएंगे।

बिहार में शून्य के पहाड़ पर समाजवादी पार्टी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी खासी हनक और धमक रखने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पड़ोसी राज्य बिहार की राजनीति में एक प्रकार की उदासीनता नजर आती है। यह दल, जो उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत जड़ें जमाए हुए है, बिहार में हमेशा से ही शून्य के पहाड़ पर खड़ा नजर आता है। यहां इसकी सफलता का इतिहास लगभग शून्य रहा है। मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित यह दल बिहार की विधान सभा में कभी भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाया। फिर भी, हाल के वर्षों में अखिलेश यादव के नेतृत्व में दल ने नई दिशा अपनाई है। अब, महागठबंधन के साथ जुड़कर अखिलेश बिहार में नई उम्मीदें जगा रहे हैं।बिहार की विधान सभा निर्वाचनों में समाजवादी दल का प्रदर्शन देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यहां इसकी स्थिति हमेशा कमजोर रही। सन 1995 के विधान सभा निर्वाचन में दल ने दो स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। उस समय बिहार की राजनीति में विभिन्न दलों का उभार हो रहा था, और समाजवादी दल ने यादव समुदाय के कुछ मतों पर कब्जा किया। लेकिन मत प्रतिशत की बात करें तो यह बहुत कम था, लगभग एक से दो प्रतिशत के बीच। उस निर्वाचन में कुल मतों का एक छोटा हिस्सा ही दल को मिला, जो इसकी सीमित पहुंच को दशार्ता है। फिर सन 2000 आया, जहां दल को कोई स्थान नहीं मिला। शून्य सीटों के साथ यह निर्वाचन दल के लिए निराशाजनक रहा। मत प्रतिशत में भी कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, और दल बिहार की मुख्य धारा से दूर होता गया। सन 2005 में दो बार निर्वाचन हुए। फरवरी में हुए निर्वाचन में समाजवादी दल ने चार स्थानों पर सफलता प्राप्त की। यह दल के लिए एक छोटी जीत थी, क्योंकि उस समय बिहार में राजनीतिक अस्थिरता थी, और विभिन्न गठजोड़ बन रहे थे। मत प्रतिशत लगभग दो प्रतिशत के आसपास रहा, जो पिछले निर्वाचनों से थोड़ा बेहतर था। लेकिन अक्टूबर में दोबारा हुए निर्वाचन में दल की सीटें घटकर दो रह गईं। फिर भी, यह दिखाता है कि दल ने यादव बहुल क्षेत्रों में कुछ प्रभाव बनाया था। लेकिन उसके बाद का इतिहास और भी निराशाजनक है। सन 2010 के विधान सभा निर्वाचन में दल को कोई स्थान नहीं मिला। मत प्रतिशत गिरकर एक प्रतिशत से भी कम हो गया। दल ने कई स्थानों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन मतदाताओं का समर्थन नहीं मिला। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (संयुक्त) जैसे दलों ने यादव मतों पर मजबूत पकड़ बना ली, जिससे समाजवादी दल हाशिए पर चला गया।सन 2015 के निर्वाचन में दल ने पचासी स्थानों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन फिर शून्य पर आकर रुक गया। मत प्रतिशत लगभग एक प्रतिशत रहा। दल ने महागठबंधन से अलग होकर लड़ने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। सन 2020 में तो दल ने निर्वाचन नहीं लड़ा, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दिया।

परिणामस्वरूप, कोई सीट नहीं जीती गई, और मत प्रतिशत की गणना भी नहीं हुई। कुल मिलाकर, 1995 से 2020 तक दल ने कुल आठ से दस सीटें ही जीतीं, और मत प्रतिशत कभी तीन प्रतिशत से ऊपर नहीं गया। यह शून्य का पहाड़ ही है, जहां दल बार-बार चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। बिहार में दल की कमजोरी का मुख्य कारण यहां की जातीय राजनीति है। यादव मतदाता मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हैं, और समाजवादी दल को उत्तर प्रदेश की तरह यहां आधार नहीं मिला।

लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है। अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश में दल के प्रमुख नेता हैं, ने बिहार में नई रणनीति अपनाई है। हाल ही में वे महागठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, बिहार में भारतीय जनता दल के विरुद्ध मजबूत मोर्चा बना रहा है। अखिलेश ने वोटर अधिकार यात्रा में भाग लिया, जो महागठबंधन द्वारा आयोजित की गई थी। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना और भारतीय जनता दल की कथित मत चोरी के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है।

अखिलेश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीय जनता दल बिहार से भागने वाला है, और महागठबंधन की जीत निश्चित है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। यह गठजोड़ बिहार के आगामी विधान सभा निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण है, जो 2025 में होने वाले हैं।अब सवाल यह है कि अखिलेश के इस कदम से किसे लाभ होगा? सबसे पहले, महागठबंधन को। बिहार में यादव मतदाता एक बड़ा हिस्सा हैं, लगभग पंद्रह प्रतिशत। राष्ट्रीय जनता दल इन मतों का मुख्य दावेदार है, लेकिन हाल के निर्वाचनों में कुछ मत बिखर गए हैं। अखिलेश, जो खुद यादव हैं और उत्तर प्रदेश में दल की हालिया लोक सभा जीत से उत्साहित हैं, इन मतों को एकजुट कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में दल ने अड़तीस स्थानों पर जीत हासिल की, जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। यह मोमेंटम बिहार में भी काम कर सकता है। महागठबंधन को इससे यादव मतों की मजबूती मिलेगी, और गैर-यादव पिछड़े वर्गों को भी आकर्षित किया जा सकता है। कांग्रेस और वामपंथी दलों को भी लाभ होगा, क्योंकि गठजोड़ मजबूत होगा। तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ने अखिलेश के इस समर्थन को स्वागत किया है। वे कहते हैं कि यह यात्रा भारतीय जनता दल को असहज कर रही है।

दूसरी ओर, समाजवादी दल को भी अप्रत्यक्ष लाभ होगा। हालांकि बिहार में दल का आधार कमजोर है, लेकिन महागठबंधन के साथ जुड़कर यह अपनी छवि मजबूत कर सकता है। अगर महागठबंधन जीतता है, तो दल को कुछ स्थानों पर अवसर मिल सकते हैं।

लेकिन मुख्य लाभ राष्ट्रीय जनता दल को होगा, क्योंकि अखिलेश का समर्थन यादव मतों को पूरी तरह उनके पक्ष में कर देगा। भारतीय जनता दल को नुकसान होगा, क्योंकि विपक्ष अब अधिक एकजुट है। बिहार में निर्वाचन हमेशा करीबी होते हैं, जैसे 2020 में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच मत प्रतिशत में केवल एक प्रतिशत का अंतर था। अखिलेश का यह कदम उस अंतर को पाट सकता है।कुल मिलाकर, यह गठजोड़ बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। शून्य के पहाड़ पर चढ़ते हुए समाजवादी दल अब महागठबंधन की सीढ़ी का सहारा ले रहा है। यह सफल होता है, तो बिहार में विपक्ष की ताकत बढ़ेगी, और भारतीय जनता दल को चुनौती मिलेगी।

क्रिकेट का महानाटक

डॉ. सुरेश कुमार

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के इस्लामाबाद स्थित प्रतिष्ठित मुख्यालय की हवा में ताजी चमेली चाय की खुशबू थी, और उससे भी ज्यादा प्रबल, आत्म-महत्व की दुर्गन्ध। चेयरमैन आजम खान, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी गरिमा उस महोगनी की मेज के आकार के सीधे अनुपात में थी जिसके पीछे वह बैठे थे, अपने बोर्ड के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। उनके सामने, एक ज्यादा बड़ा, चमकदार विश्व मानचित्र था, जिसके लाल और नीले पिन वैश्विक क्रिकेट शक्ति के उतार-चढ़ाव को दर्शा रहे थे, मानो उसकी अपनी कोई धड़कन हो। उन्होंने घोषणा की, यह समय है कि पीसीबी अपनी भू-राजनीतिक महत्ता को फिर से स्थापित करे। यह अवसर, जाहिर है, आने वाला क्रिकेट विश्व कप था, एक ऐसी विशालकाय घटना जो पाकिस्तान की स्पष्ट, और हाँ, बहुत अधिक अनुरोधित भागीदारी के बिना संभव ही नहीं थी। उनकी रणनीति, जो देर रात के सत्रों और अनगिनत प्यालों में चाय की चुस्कियों के साथ सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी, रणनीतिक उदासीनता की एक उत्कृष्ट रचना थी। वे अनासक्ति का अभिनय करेंगे। वे 'सुरक्षा चिंताओं' का संकेत देंगे, एक ऐसा वाक्यांश जो, उनके दिमाग में, एक परमाणु मिसाइल के प्रक्षेपण के राजनयिक समकक्ष था, जो पूरे क्रिकेट जगत को घुटनों पर लाने की गारंटी देता था। मिस्टर खान ने अपनी ठोड़ी को एक वीर कोण पर झुकाकर योजना प्रस्तुत कीः भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) घबरा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) गिड़गिड़ाएगी, और सम्मान का एक नया युग, और शायद एक बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन, शुरू होगा।

पूरे कमरे ने गंभीर सहमति में सिर हिलाया। योजना त्रुटिहीन थी, खेल शुरू होने से पहले ही शह और मात। वे सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड नहीं थे; वे वैश्विक वातार्कार थे, और विश्व कप उनका मंच था। एक दिन बाद, दुनिया भर के मीडिया कर्मी जमा थे, अटकलों से गुंजायमान। मिस्टर खान मंच पर आए, किसी सामान्य बयान के साथ नहीं, बल्कि एक राजनेता की शांत गरिमा के साथ, जिसे किसी त्रासदी की घोषणा करने के लिए मजबूर किया गया हो।बहुत भारी मन और गहरे खेद के साथ, उन्होंने शुरू किया, उनकी आवाज एक नीची, दुखद गड़गड़ाहट थी, हम आपको अपने निर्णय से अवगत कराना चाहते हैं। उन्होंने नाटकीय प्रभाव के लिए एक क्षण का विराम लिया, जिससे प्रेस दल की सामूहिक साँसें गले में अटक गईं। हमारे खिलाड़ियों के सामने अभूतपूर्व और स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य सुरक्षा खतरों के कारण, हमने यह निर्धारित किया है कि हम, अच्छे विवेक से, अपनी टीम को भारत में विश्व कप के लिए नहीं भेज सकते।

उन्होंने अस्पष्ट खतरों को सूचीबद्ध कियाः अनिर्दिष्ट रसद संबंधी खतरे, अस्तित्व संबंधी खिलाड़ी सुरक्षा चिंताएं, और एक सामान्य वातावरण... खैर, चलिए, तनाव का। उन्होंने कैमरों की ओर देखा, अपनी ही धार्मिकता के बोझ से दबे हुए एक आदमी की तरह। सुर्खियां खुद ही बन गईं। पाकिस्तान पीछे हटा!, विश्व कप खतरे में!, सुरक्षा भय ने वैश्विक क्रिकेट को हिलाया! कमरा चमकती कैमरों और चिल्लाते पत्रकारों की गूँज से भर गया, हर कोई एक बयान के लिए बेताब था। मिस्टर खान ने, इस्तीफे की एक अभ्यास की हुई आह के साथ, उन्हें वह दिया जो वे चाहते थे। वह सिद्धांतों के आदमी थे, अपने खिलाड़ियों के रक्षक थे, और यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था को इसके परिणामस्वरूप एक मामूली मंदी का सामना करना पड़ा, तो यह ऐसी नैतिक स्पष्टता के लिए एक छोटा सा मूल्य था। वह अपने कार्यालय में लौटे, दुनिया का भार अपने कंधों पर महसूस करते हुए, एक ऐसा भार जिसे वह पूरी तरह से न्यायसंगत मानते थे।

पीसीबी के कमांड सेंटर में वापस, फोन एक मखमली कपड़े पर कीमती कलाकृतियों की तरह रखे गए थे। प्रत्येक बोर्ड सदस्य को एक फोन सौंपा गया था, एक मूक संतरी जो क्रिकेट जगत से आने वाली, अपरिहार्य, बेचैन गुहारों का इंतजार कर रहा था। मिनट एक घंटे में, और फिर दो घंटे में फैल गए। कमरा इतना शांत था कि आप एयर कंडीशनर की धीमी आवाज और मिस्टर खान के पॉलिश किए हुए जूते की फर्श पर तालबद्ध खट-खट की आवाज सुन सकते थे।

वह टहलते रहे, कभी-कभी शांत फोनों को ऐसे देखते जैसे वे उन्हें धोखा दे रहे हों। कोई कॉल आई? उन्होंने कमरे से अपनी आवाज में एक नीची फुसफुसाहट के साथ पूछा। क्या आईसीसी से कोई हताश गुहार है? बीसीसीआई से कोई घबराया हुआ ईमेल? एक जूनियर विश्लेषक, एक युवा व्यक्ति जिसे कमरे में होने का दुर्भाग्य था, ने डरते-डरते अपना हाथ उठाया। सर, हमें बीसीसीआई से एक ईमेल मिला है।

भारत-चीन ने परस्पर भागीदारी बढ़ने पर दिया बलः मिस्री

एजेंसी

तिआनजिन। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देशों के संबंधों के भविष्य की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसमें दोनों के बीच 'भागीदारी' बढ़ने पर बल है ना कि प्रतिद्वंद्विता पर। श्री मिस्री श्री मोदी की चीन यात्रा के दौरान उनके विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि श्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (सीएसओ) शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को कल संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने आज दिन में चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में कजान के बाद दोनों नेता एक साल में दूसरी बार मिले हैं।श्री मिस्री ने बताया कि श्री मोदी कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उन्होंने भारत- चीन संबंध पर एक सवाल के जवाब में कहा कि दोनों नेताओं ने बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि हमें जिस भविष्य की कामना करनी चाहिए, जिसके लिए लक्ष्य करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए , वह भागीदारी का भविष्य है ना कि प्रतिद्वंद्विता का। उन्होंने कहा कि भारत- चीन सीमा पर साओ की तैनाती एक वास्तविकता है, लेकिन लगता है कि पिछले एक साल में जिस तरह की स्थितियां बनी है उसे सीमा पर स्थित यदि सामान्य नहीं हुई है तो भी सामान्य की ओर बढ़ रही है।

चीन बेलारूस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैः शी जिनपिंग

तियानजिन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वह बेलारूस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। श्री जिनपिंग ने उत्तरी चीनी शहर तियानजिन में बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की। गौरतलब है कि श्री लुकाशेंको शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन (एससीओ) 2025 में भाग लेने को अभी चीन में हैं और जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जनप्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ में भी भाग लेंगे। चीनी राष्ट्रपति ने मानवता के दोराहे पर खड़े होने का हवाला देते हुए कहा कि वह सच्चे बहुपक्षवाद के पालन के लिए बेलारूस के साथ मिलकर काम करने और विश्व शांति, विकास तथा परस्पर लाभकारी सहयोग में संयुक्त रूप से योगदान देने को तैयार है। जबकि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने चीन को ऐसा सदाबहार साझेदार बताया जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। श्री जिनपिंग ने कहा कि चीन और बेलारुस के लोगों ने कभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। बेलारूस ने सैन्यवाद और फासीवाद को कुचलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और एक गहरी दोस्ती कायम की थी।।

ऑस्ट्रेलिया में चोरी की कार की टक्कर में दो लोगों की मौत

सिडनी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन के उत्तर में एक चोरी की कार की टक्कर में तीन वाहनों के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। क्वींसलैंड पुलिस ने बताया कि ब्रिस्बेन से 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित चैट्सवर्थ नामक छोटे से शहर के पास करीब 3 बजे हुई इस दुर्घटना की सूचना आपातकालीन सेवाओं को दी गई। शुरुआती पुलिस जाँच से पता चलता है कि एक चोरी की गई काली सेडान तेज़ गति से खतरनाक तरीके से वाहनों को ओवरटेक कर रही थी, तभी उसकी टक्कर एक दूसरी काली सेडान से हो गई। चोरी की कार ने फिर एक और कार, एक सिल्वर सेडान, को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियाँ पलट गईं और सिल्वर सेडान में आग लग गई। चोरी की गई कार के 20 वर्षीय पुरुष चालक और सिल्वर सेडान के 50 वर्षीय पुरुष चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। क्वींसलैंड पुलिस सेवा ने कहा कि फोरेंसिक दुर्घटना इकाई दुर्घटना की परिस्थितियों की जाँच कर रही है। क्वींसलैंड के रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब के अनुसार, 2025 तक क्वींसलैंड में सड़क दुर्घटनाओं में 200 मौतें हो चुकी हैं, और राज्य 2009 के बाद से अपनी उच्चतम वार्षिक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दर्ज करने की राह पर है।

यूक्रेन की संसद के पूर्व अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या

कीव। यूक्रेन की संसद के पूर्व अध्यक्ष एंड्री पारुबिय की शनिवार को पश्चिमी शहर ल्वीव में गोली मारकर हत्या कर दी गई।यूक्रेनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यूक्रेनी अभियोजक जनरल कार्यालय ने कहा कि एक अज्ञात बंदूकधारी ने गोलीबारी की और 54 वर्षीय राजनेता की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार, पुलिस संदिग्ध की तलाश कर रही है, जो डिलीवरी राइडर का वेश धारण करके इलेक्ट्रिक बाइक पर भाग गया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस हत्या की निंदा करते हुए इसे 'भयावह हत्या' बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा,'हत्यारे की तलाश और जाँच में सभी आवश्यक बल और साधन लगे हुए हैं।पारुबिय यूक्रेन के 2004 और 2014 के विरोध आंदोलनों में एक प्रमुख व्यक्ति थे और कुछ समय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव भी रहे। पूर्व यूक्रेनी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने इस हत्या को 'यूक्रेन के दिल पर मारी गई गोली' कहा।

वीडियो ऑफ द डे : रूस ने शेयर किया पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात का खास वीडियो

एजेंसी

तियानजिन । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले एक साथ मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात का वीडियो शेयर किया और इसे 'वीडियो ऑफ द डे' बताया।

रूस के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। मंत्रालय ने लिखा, 'एससीओ शिखर सम्मेलन की शुरुआत से ठीक पहले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस पल को

'वीडियो ऑफ द डे' बताया। तीनों नेताओं की यह मुलाकात एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सम्मेलन के फोटो सेशन में विश्व नेताओं के साथ हिस्सा लिया था, जो क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन से पहले एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक क्षण रहा।इस तस्वीर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य सदस्य देशों के नेता भी शामिल थे। पीएम मोदी ने फोटो सेशन से जुड़ी तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में।' शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति शी और पुतिन के साथ बातचीत करते नजर आए, जो सक्रिय कूटनीति की वापसी का संकेत देता है। बता दें कि चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट से कहा - बर्खास्तगी की प्रक्रिया 'पूरी तरह अवैध'

एजेंसी

नई दिल्ली। इजराइल की अटॉर्नी जनरल गली बहारीव-मियारा ने हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं के जवाब में कहा है कि सरकार द्वारा उन्हें पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया 'पूरी तरह अवैध' है। बहारीव-मियारा ने अपने बयान में कहा, 'सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल समाप्त करने के नियमों में बदलाव किया, और यह बदलाव तब किया जब बर्खास्तगी की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। यह सिर्फ परिणाम सुनिश्चित करने के लिए किया गया।' उनके अनुसार, सरकार ने मौजूदा कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाते हुए एक मंत्रिस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया, ताकि वही समिति बर्खास्तगी की सिफारिश कर सके। हाई कोर्ट इस मामले पर इस सप्ताह के अंत में सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि अदालत ने सरकार के मतदान के तुरंत बाद बहारीव-मियारा की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी।

टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 'खरबों डॉलर' आए - डोनाल्ड ट्रंप

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 'खरबों डॉलर' आए हैं। यह बयान उस समय आया है, जब एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया था कि उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाकर अपने राष्ट्रपति पद के अधिकार का अतिक्रमण किया है। ट्रंप ने अपने 'व्यापार एजेंडे' का बचाव करने के लिए ट्रुथ सोशल का सहारा लिया। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, 'अमेरिका में कीमतें बहुत कम हैं, जबकि मुद्रास्फीति लगभग शून्य है। हास्यास्पद, भ्रष्ट राजनेताओं से अनुमोदित 'पवन चक्कियों' को छोड़कर, जो उनका उपयोग करने वाले हर राज्य और देश को बर्बाद कर रही हैं, ऊर्जा की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। पेट्रोल कई वर्षों के निचले स्तर पर है। यह सब शानदार टैरिफ के बावजूद है, जो उन देशों से खरबों डॉलर ला रहे हैं, जिन्होंने दशकों तक हमारा पूरा फायदा उठाया और अमेरिका को फिर से मजबूत और सम्मानित बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह टिप्पणी उनके

प्रशासन की व्यापार नीतियों को लगे एक बड़े कानूनी झटके के बाद आई है अमेरिकी अपीलीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान एकतरफा तथाकथित 'पारस्परिक शुल्क' लगाकर अपने राष्ट्रपति पद के अधिकार का अतिक्रमण किया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शुल्क लगाने का अधिकार 'विशेष रूप से? कांग्रेस के पास है, जो कराधान और व्यापार पर उसके संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने विशेष रूप से ट्रंप के 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के इस्तेमाल पर ध्यान दिया और कहा कि यह राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन शुल्क या कर लगाने का अधिकार नहीं देता। खास बात यह है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा और प्रशासन को अपील करने का अवसर देने के लिए इसे 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस फैसले के जवाब में, ट्रंप ने संकेत दिया कि वह इस मामले को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक राष्ट्रपति की शक्तियों को कमजोर करता है।

अमेरिकी न्यायाधीश ने ग्वाटेमाला भेजे जाने वाले नाबालिग प्रवासी बच्चों की निर्वासन प्रक्रिया रोकी

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को ग्वाटेमाला भेजे जाने वाले 10 नाबालिग प्रवासी बच्चों की तत्काल निर्वासन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ये बच्चे 10 से 17 साल की उम्र के हैं और बिना माता-पिता या अभिभावक के अमेरिका में प्रवेश किए थे। जिला न्यायाधीश स्पार्कल सूकनन ने आदेश जारी करते हुए 14 दिनों के लिए निर्वासन रोकने का निर्देश दिया और दोपहर में तत्काल सुनवाई का समय तय किया। अदालत का कहना था कि बच्चों को निर्वासित करने की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी थी, जो अमेरिकी कानून का उल्लंघन प्रतीत होती है। यह आदेश नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर की ओर से दायर की गई याचिका के बाद आया। याचिका में दावा किया गया कि इन बच्चों को ग्वाटेमाला भेजना उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा और इससे उन्हें अत्याचार, उत्पीड़न या खतरे का सामना करना पड़ सकता है। शिकायत में कहा गया कि प्रशासन

जिला न्यायाधीश स्पार्कल सूकनन ने आदेश जारी करते हुए 14 दिनों के लिए निर्वासन रोकने का निर्देश दिया और दोपहर में तत्काल सुनवाई का समय तय किया।

बच्चों को अवैध रूप से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) की कस्टडी में भेजने और ग्वाटेमाला के लिए उड़ानों पर चढ़ाने की योजना बना रहा था। सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने ग्वाटेमाला के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत अमेरिका में बिना अभिभावक पहुंचे बच्चों को ग्वाटेमाला भेजा जा सकता है। यह प्रक्रिया इस सप्ताहांत से शुरू करने की योजना थी।

मौजूदा अमेरिकी कानून के अनुसार, बिना माता-पिता के सीमा पार करने वाले बच्चों को फेडरल शेल्टर में रखा जाता है, जब तक कि उन्हें परिवार या फोस्टर होम में नहीं भेजा जाता। लेकिन हाल ही में ऑफिस ऑफ रिफ्यूजी रीसैटलमेंट की निदेशक मेलिसा जॉनस्टन ने स्टाफ को ईमेल भेजकर ग्वाटेमाला के बच्चों की रिहाई रोकने का निर्देश दिया था, सिवाय उन मामलों के जहां माता-पिता या कानूनी अभिभावक अमेरिका में मौजूद हैं। ग्वाटेमाला के विदेश मंत्रालय और अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

एससीओ शिखर सम्मेलन : सदस्य देशों ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, कहा- दोहरे मापदंड अस्वीकार्य

एजेंसी

तियानजिन । चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दरअसल, एससीओ शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन खतरों का निजी या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। सदस्य देशों ने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में संप्रभु राष्ट्रों और उनकी सक्षम संस्थाओं की अग्रणी भूमिका को

मान्यता दी। इस अवसर पर कहा गया कि सदस्य देश सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। वे जोर देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं। साथ ही, वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह आतंकवाद से मिलकर लड़े, जिसमें सीमापार आतंकियों की आवाजाही भी शामिल है। एससीओ बैठक में भारत की पहल को मान्यता दी गई। घोषणापत्र में 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की थीम को समर्थन दिया गया। इसके अलावा, सदस्य देशों ने 3 से 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 5वें एससीओ स्टार्टअप फोरम के परिणामों का स्वागत किया। इस मंच ने वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों व इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को गहराई देने में अहम भूमिका निभाई है।

साथ ही, 21 और 22 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 20वें एससीओ थिंक टैंक फोरम के आयोजन को सराहा गया। इसके अलावा, भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में स्थापित एससीओ अध्ययन केंद्र के सांस्कृतिक और मानवीय आदान-प्रदान को मजबूत करने में योगदान को मान्यता दी गई।

अमेरिका में हुआ भयानक प्लेन हादसा

एजेंसी

फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल। अमेरिका के फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के पास दो छोटे विमान हवा में आपस में भिड़ गए। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। अमेरिका में एक और विमान हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार, कोलोराडो के फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के रनवे पर दो विमान आपस में टकरा गए। टक्कर के तुरंत बाद दोनों विमानों में आग भड़क उठी और वे जमीन पर गिर गए। इनमें से एक विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जबकि दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में लगभग 3 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इस घटना की पुष्टि मॉर्गन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने की है।

मुहम्मद यूनुस गुट ने बांग्लादेश को बनाया जीता-जागता नर्क : अवामी लीग

एजेंसी

ढाका । बांग्लादेश अवामी लीग ने सोमवार को देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक जातीय पार्टी (जापा) के कार्यालय पर हुए हमले, तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की कड़ी निंदा की। मीडिया के मुताबिक, शनिवार शाम को ढाका के ककरैल स्थित जापा के केंद्रीय कार्यालय पर हमला किया गया और उसमें आग लगा दी गई। यह घटना उसी इलाके में पार्टी के कार्यकर्ताओं और गोनो अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़पों के एक दिन बाद हुई।

हमले के बाद, जापा अध्यक्ष के प्रेस सचिव और संयुक्त महासचिव खांडेकर देलवर जलाली ने कहा, ÷हमलावरों ने ककरैल स्थित जातीय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आग लगा दी। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर स्थित लाइब्रेरी की किताबें, महत्वपूर्ण

दस्तावेज और फर्नीचर जला दिए।

खांडेकर देलवर जलाली ने कहा, यह हमला जातीय पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्रम समाप्त करने और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुरोध पर ऑफिस खाली करने के बाद हुआ। इसके बाद आए लगभग 20 से 30 लोगों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए अवामी लीग ने आरोप लगाया कि इस सरकार की शह पर बांग्लादेश में भीड़-आतंकवाद बेरोकटोक चल रहा है। लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं और अंतरिम सरकार चुप है। देशभर में एक के बाद एक अजीबो-गरीब और भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। अवामी लीग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इन घटनाओं के पैटर्न को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि फांसीवादी यूनुस गुट जानबूझकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है या इसमें पूरी तरह से उदासीनता दिखा रहा है।पार्टी का कहना है कि केवल एक लालची सरकार ही जिसमें लोगों के प्रति कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी की भावना न हो, इतने लापरवाह तरीके से सत्ता पर काबिज हो सकती है।

आस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को बनाया गया निशाना, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नव-नाजी आंदोलन की निंदा की

एजेंसी

कैनबरा। आस्ट्रेलिया में भी भारत विरोधी बयार बहने की खबर आ रही है। वहां बसे भारतीय समुदाय के लोगों को आस्ट्रेलिया के लिए खतरा बताया जा रहा है और उसके खिलाफ नव-नाजी, नस्लवादी किस्म का आंदोलन चलाया जा रहा है। हालांकि आस्ट्रेलिया की सरकार ने नव-नाजी 'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' आंदोलन की कड़ी निंदा की है और प्रदर्शनकारियों द्वारा आयोजित आव्रजन विरोधी रैलियों को नव-नाजी सहानुभूति, नस्लवाद और नफरत से जोड़कर देखा है। ये रैलियां मेलबर्न, सिडनी, केर्न्स, ब्रिस्बेन जैसे बड़े शहरों में आयोजित की गई और उनमें जमकर ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय को निशाना पर लिया गया। इन रैलियों के बाबत ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ मंत्री मरे वाट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम सिडनी में हो रही मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैली की कड़ी निंदा करते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव बढ़ाना नहीं है। श्री वाट ने कहा, हम ऐसी रैलियों का समर्थन नहीं करते जो नफरत फैलाने और हमारे समुदाय को विभाजित करने के लिए आयोजित की जाती हैं। उन्होंने इन रैलियों को नव-नाजी समूहों द्वारा प्रायोजित और प्रचारित बताया। बहुसांस्कृतिक मामलों की मंत्री ऐनी एली ने कहा कि सरकार सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ खड़ी है। भले ही वे कहीं भी क्यों नहीं पैदा हुए हों। उनकी यह टिप्पणी उन लोगों के खिलाफ है जो लोगों को बांटना और प्रवासी समुदायों को डराना चाहते हैं। विपक्षी नेता सुज़ैन ले ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आव्रजन विरोधी प्रदर्शनों से पहले शांति और सम्मानजनक व्यवहार का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन नस्लवाद और अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि इन रैलियों और प्रदर्शनों में विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय को निशाना बनाया गया, जो आस्ट्रेलिया की वर्तमान जनसंख्या का तीन प्रतिशत है। इस पोस्टर में लिखा था कि पांच वर्षों में भारतीयों की संख्या 100 वर्षों में इटालियंस और यूनानियों से ज्यादा होगी। प्रदर्शनकारियों ने इसके अतिरिक्त लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली देश की वामपंथी सरकार की भी आलोचना की और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से पद छोड़ने की मांग की।

इजराइली हमले में हमास का प्रवक्ता अबू उबैदा ढेर, आईडीएफ ने की पुष्टि

एजेंसी

तेल अवीव। इजराइल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने पुष्टि की है कि हाल ही में किए गए हवाई हमले में हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की मौत हो गई है। उबैदा को हमास की 'प्रचार मशीन' का मुख्य चेहरा माना जाता था। आईडीएफ के अनुसार यह अभियान

शिन बेट की ऑपरेशन यूनिट और साउदर्न कमांड के समन्वय से संचालित हुआ। खुफिया एजेंसियों की पूर्व जानकारी के आधार पर उस ठिकाने की पहचान की गई, जहां अबू उबैदा छिपा हुआ था। पिछले एक दशक से उबैदा हमास के सैन्य विंग के प्रचार तंत्र का नेतृत्व कर रहा था। इस दौरान उसने संगठन की मीडिया रणनीतियों को दिशा दी और विभिन्न ब्रिगेड एवं बटालियनों में प्रवक्ता गतिविधियों का संचालन किया। बताया जाता है कि वह राजनीतिक और सैन्य विंग के बीच मीडिया तालमेल का भी मुख्य जिम्मेदार था। आईडीएफ का कहना है कि हमास का यह प्रोपेगेंडा विंग 07 अक्टूबर के हमले की भीषणता को फैलाने और बंधकों के वीडियो जारी करने के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा उबैदा के नेतृत्व में बनाए गए वीडियो अरब दुनिया में आतंकी गतिविधियों को भड़काने के उद्देश्य से प्रसारित किए जाते थे।

मोदी-जिनपिंग ने लिया भारत-चीन संबंधों को सहयोग की पटरी पर लाने का संकल्प

एजेंसी

तियान्जिन (चीन)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज यहां बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों ने सीमा मसले के समाधान के लिए संस्थागत प्रणाली एवं रणनीतिक संवाद को और प्रभावी बनाने के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटे को संतुलित बनाने के निर्णय लिये। दोनों नेताओं ने माना कि एक एशियाई शताब्दी बनाने के लिए एक कार्यशील बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके केंद्र में एक बहुध्रुवीय एशिया हो। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की जानकारी देने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, प्रधानमंत्री यहां होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए तियान्जिन की यात्रा पर हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक में हुई। हमने उस बैठक पर एक बयान जारी किया। एक साल से भी कम समय में दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी बैठक थी। उनकी पिछली बैठक पिछले साल अक्टूबर में कजान में हुई थी, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए कुछ रणनीतिक दिशानिर्देश निर्धारित किए थे और दोनों पक्षों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया था।

उन्होंने कहा कि वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि दोनों देश मुख्य रूप से अपने घरेलू विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और इसमें वे प्रतिद्वंद्वियों के बजाय भागीदार थे। यह उनके बीच आम सहमति का एक तत्व भी था कि भारत और चीन के बीच एक स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध दोनों देशों में रहने वाले 2.8 अरब लोगों के लाभ के लिए हो सकता है। मिस्री ने कहा, दोनों नेताओं को यह जानकर खुशी हुई कि कजान में बैठक के बाद से जो कार्रवाई की गई, उसके बाद से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई है, विशेष रूप से लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सिद्धांतों के बारे में अपनी-अपनी समझ के बारे में बात की, जिससे दोनों पक्षों के भविष्य के कार्यों का मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी क्योंकि हम संबंधों के अन्य पहलुओं पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साझा हित उनके मतभेदों से अधिक हैं और दोनों नेताओं ने इस तथ्य पर भी सहमति व्यक्त की कि मतभेदों को विवादों में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह भी समझा गया कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन विकास करें और सहयोग करें। विदेश सचिव ने कहा, सीमा का मुद्दा भी चर्चा में आया। दोनों नेताओं ने पिछले साल सफल विघटन और तब से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर ध्यान दिया। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर और सुचारू विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। मौजूदा तंत्रों का उपयोग करके सीमाओं पर शांति बनाए रखने और आगे चल रहे समग्र संबंधों में गड़बड़ी से बचने की आवश्यकता पर समझ थी। राष्ट्रपति शी ने द्विपक्षीय संबंधों को और उन्नत करने के लिए चार सुझाव दिए, अर्थात् रणनीतिक संचार को मजबूत करना और आपसी विश्वास को गहरा करना, आदान-प्रदान और सहयोग का विस्तार करना, आपसी लाभ प्राप्त करना और जीत के परिणाम प्राप्त करना, एक-दूसरे की चिंताओं को समायोजित करना, और अंत में साझा हितों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और इन सभी का प्रधानमंत्री मोदी ने सकारात्मक जवाब दिया। मिस्री ने कहा कि नेताओं ने अपने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक दृष्टिकोण से और दोनों लोगों के दीर्घकालिक हितों में सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अन्य मुद्दों के अलावा, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और संतुलित करने, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने, सीमा पार की नदियों पर सहयोग करने और संयुक्त रूप से आतंकवाद से लड़ने के तरीकों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। आपसी सम्मान, आपसी हितों और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर इन सभी मुद्दों पर अतिरिक्त प्रगति करने की इच्छा थी।

अगस्त में और तेज हुई विनिर्माण की रफ्तार

एजेंसी

मुंबई। देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी अगस्त में भी बरकरार रही तथा सोमवार को जारी एचएसबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इसकी रफ्तार और तेज हो गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र के खरीद प्रबंधकों के बीच सर्वेक्षण पर आधारित पीएमआई सूचकांक जुलाई के 59.1 से बढ़कर अगस्त में 59.3 पर पहुंच गया जो 17 साल से अधिक की सबसे तेज रफ्तार को दिखाता है। साथ ही उत्पादन की मात्रा में लगभग पांच साल की सबसे बड़ी तेजी देखी गयी। नये ऑर्डरों में भी 57 महीने की सबसे तेज बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। पीएमआई सूचकांक माह-दर-माह आधार पर जारी किया जाता है। इसका 50 प्रतिशत से ऊपर रहना वृद्धि को और इससे कम रहना गिरावट को दर्शाता है। वहीं, सूचकांक का 50 पर रहना स्थिरता को दिखाता है। भारत में एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, उत्पादन में तेज वृद्धि के दम पर भारत का विनिर्माण पीएमआई अगस्त में एक और नयी ऊंचाई पर पहुंच गया। अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क का विदेशों से मिलने वाले ऑर्डर में हल्की कमी में योगदान रहा होगा क्योंकि अमेरिकी खरीदारों ने अनिश्चितता के बीच ऑर्डर देने से परहेज किया होगा। हालांकि कुल मिलाकर ऑर्डर में काफी अच्छी वृद्धि हुई है जो घरेलू मांग की मजबूती को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्डरों में लगभग जुलाई के समान ही वृद्धि देखी गयी।

विमान ईंधन सस्ता, वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम भी घटे

नई दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार से विमान ईंधन और वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में विमान ईंधन 1,308.41 रुपये यानी 1.42 प्रतिशत सस्ता होकर आज से 90,713.41 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है। इससे पहले लगातार दो महीने इसके दाम घटाये गये थे। कोलकाता में विमान ईंधन 1,278.72 रुपये (1.34 प्रतिशत) सस्ता होकर अब 93886.18 रुपये और मुंबई में 1,244.31 रुपये (1.45 प्रतिशत) सस्ता होकर 84,832.83 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है। चेन्नई में इसमें 1,360.30 रुपये यानी 1.42 प्रतिशत की कटौती की गयी है और अब यह 94,151.96 रुपये प्रति किलोलीटर बिकेगा। वहीं, 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम 51.50 रुपये तक घटाये गये हैं। अप्रैल से अब तक लगातार छठी बार इसमें कटौती की गयी है जबकि घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को अप्रैल के बाद राहत नहीं मिली है। दिल्ली और चेन्नई में वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर 51.50 रुपये सस्ता होकर क्रमशः 1,580 रुपये और 1,738 रुपये का हो गया है। कोलकाता में यह 50.50 रुपये और मुंबई में 51 रुपये सस्ता हुआ है। आज से कोलकाता में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 1,684 रुपये का और मुंबई में 1,531.50 रुपये का मिलेगा।

एक सप्ताह में रुपया 0.65 प्रतिशत टूटा, ऐतिहासिक निचले स्तर पर

मुंबई। विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय पूंजी बाजार में बिकवाली और घरेलू शेयर बाजारों में रही गिरावट के दबाव में रुपया बीते सप्ताह 56.50 पैसे (0.65 प्रतिशत लुढ़ककर) अंतिम कारोबारी दिवस पर 88.09 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। भारतीय मुद्रा पहली बार 88 रुपये प्रति डॉलर से नीचे बंद हुई है। इससे पहले इसका निचला स्तर 87.88 रुपये प्रति डॉलर था। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी बाजार में भारी बिकवाली से डॉलर की मांग बढ़ी है जिससे रुपया दबाव में आ गया।

56 करोड़ जन धन खातों में 13 करोड़ निष्क्रिय

नई दिल्ली। देश में पिछले 11 साल में खोले गये 56 करोड़ जन धन खातों में से 13 करोड़ निष्क्रिय हो गये हैं यानी उनमें दो साल या उससे अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से संसद के हाल में समाप्त सत्र में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी गयी है। इसे देखते हुए इन निष्क्रय खातों की पुनः केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार ने 01 जुलाई से ग्राम पंचायत स्तर पर संतृप्ति अभियान शुरू किया गया है जो 30 सितंबर तक चलेगा। इस साल 31 जुलाई तक देश में जन धन खातों की संख्या 56,03,84,490 थी जिनमें 13,04,52,845 खाते निष्क्रिय थे। यह कुल खातों के 23 प्रतिशत से अधिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 9,98,47,121 जन धन खाते खोले गये हैं और वहां निष्क्रिय खातों की संख्या 2,75,04,107 (27 प्रतिशत से अधिक) है। इसके बाद बिहार में 6,47,91,296 जन धन खातों में से 1,39,00,934 निष्क्रिय हैं। पश्चिम बंगाल में 5,42,25,684 जन धन खातों में से 88,35,398 निष्क्रिय हैं जबकि मध्य प्रदेश में 4,58,29,191 में से निष्क्रिय जन धन खातों की संख्या 1,07,06,565 है।

सरकार ने एक सितंबर से बदले नियम-अब चांदी के गहनों की भी होगी हॉलमार्किंग

एजेंसी

नई दिल्ली। सोने के गहनों की हॉलमार्किंग का नियम लागू होने के बाद अब केंद्र सरकार ने चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्किंग की तैयारी कर ली है। केंद्र का इरादा सोने के गहनों की तरह ही चांदी के गहनों की शुद्धता की गारंटी की जानकारी भी ग्राहकों तक पहुंचाने की है। चांदी के गहनों की शुद्धता की गारंटी के लिए कल यानी 1 सितंबर से हॉल मार्किंग का नियम लागू हो जाएगा। सरकार अभी चांदी के गहनों पर हॉल मार्किंग के नियम को अनिवार्य नहीं कर रही है। फिलहाल हॉल मार्किंग का ये नियम वॉलंटरी होगा। यानी गहने खरीदने वाले ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो हॉलमार्क वाला चांदी का गहना खरीदे या बिना हॉलमार्क वाला गहना खरीदे। चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 6 नए स्टैंडर्ड 800, 835, 900, 925, 970 और 990 तय किए हैं। अब हर हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एक 6 अंकों का यूनिक कोड (एचयूआईडी) भी होगा। इस कोड से तुरंत पता चल जाएगा कि चांदी के गहने की शुद्धता कितनी है। ये सिस्टम पुराने हॉलमार्किंग तरीके की जगह लेगा और इससे बाजार में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। हॉलमार्किंग का नियम लागू हो जाने के बाद अब चांदी के गहनों के ग्राहक आसानी से बीआईएस केयर ऐप पर जाकर वेरिफाई एचयूआईडी फीचर की मदद से चेक कर सकेंगे कि गहनों पर अंकित कोड असली है या नकली। हॉलमार्किंग से ये बात भी तय हो जाएगी कि चांदी की शुद्धता उतनी ही है, जिसके लिए ग्राहक पैसा चुका रहा है। इससे चांदी के गहनों की खरीदारी पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगी।दरअसल, साल 2021 में केंद्र सरकार ने सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था।

इसी तर्ज पर अब चांदी की ज्वेलरी के लिए भी ये सिस्टम लाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सर्राफा बाजार को ज्यादा पारदर्शी बनाना और ग्राहकों को असली उत्पाद उपलब्ध कराना है। हॉलमार्किंग शुरू हो जाने के बाद चांदी के गहनों के ग्राहक भी किसी भी घोखाधड़ी से बच सकेंगे।

अगस्त में एफपीआई ने की जमकर बिकवाली, एक महीने में 34,993 करोड़ रुपये निकाले

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के कारोबार के लिहाज से अगस्त का महीना काफी बुरा साबित हुआ। इस महीने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयर बाजार से 34,993 करोड़ रुपये यानी करीब चार अरब डॉलर की निकासी कर ली। फरवरी के बाद पहली बार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने घरेलू शेयर बाजार से इतनी बड़ी मात्रा में अपने पैसे निकाले हैं।

फरवरी के महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 34,574 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। अगस्त के पहले जुलाई के महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने घरेलू शेयर बाजार में 17,741 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। इस तरह अगस्त के महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई की तुलना में करीब दोगुना बिकवाली की है। साल 2025 में जनवरी से लेकर अगस्त तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक घरेलू शेयर बाजार से 1.30 लाख करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। धामी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत धामी का कहना है कि घरेलू शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली के लिए वैश्विक स्तर पर बनी पर प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ ही घरेलू स्तर पर भी कई कारणों को जिम्मेदार माना जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की वजह से निवेशकों के सेंटीमेंट्स प्रभावित हुए हैं। भारी भरकम टैरिफ की वजह से भारत की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और ग्रोथ आउटलुक को लेकर आशंका बढ़ गई है।

ईडी ने करीब 697 करोड़ रुपये से जुड़े घोटाले में अमित अग्रवाल को किया गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उन्होंने देश से 696.69 करोड़ रुपये की अवैध हेराफेरी से जुड़े धन शोधन के एक बड़े मामले में कथित प्रमुख संचालक अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के बाद आरोपी को पीएमएलए अदालत के सामने पेश किया गया, जहां उसे सात दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच से जुड़ी है। ईडी की पीएमएलए जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू हुई है। एफआईआर में किंजल फ्रेट फॉरवर्डिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों पर भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र समेत गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। शुरुआती आरोप था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास मोहपाल ने अपने प्रमाण-पत्रों का गलत इस्तेमाल कर अहम दस्तावेज फॉर्म 15सीए और 15सीबी की जालसाजी की, जो विदेशी धन प्रेषण को अधिकृत करने के लिए आयकर विभाग द्वारा जरूरी थे। जांच में सामने आया कि आरोपी संस्थाओं ने माल, सेवाओं और माल ढुलाई शुल्क के आयात के भुगतान के नाम पर धोखाधड़ी कर हांगकांग और सिंगापुर में 696.69 करोड़ रुपये भेजे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लेन-देन में भारत को कभी कोई सामान या सेवा नहीं दी गई। इससे देश को विदेशी मुद्रा का भारी नुकसान हुआ। संस्थाओं के मालिकों ने इस घोटाले को अंजाम देने के लिए एक जटिल नेटवर्क वाली शेल कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों के बैंक खाते खोलने के लिए निदेशक और साझेदारों के सभी

पहचान पत्र फर्जी इस्तेमाल किए गए। इस कार्यप्रणाली में नकदी के बदले में इन खातों में फर्जी जमा प्रविष्टियां दर्ज की गईं। इसके बाद, फर्जी एयरवे बिल, चालान तथा महत्वपूर्ण जाली फॉर्म 15सीबी प्रमाणपत्र जैसे जाली दस्तावेजों का उपयोग करके धनराशि को अवैध रूप से भारत के बाहर भेजा गया। ईडी ने अपनी जांच में अमित अग्रवाल को इस ऑपरेशन के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक बताया। उन पर फर्जी संस्थाओं का जाल बिछाने, जाली पहचान पत्रों का उपयोग करके बैंक खाते खोलने और नकद-आधारित जमा प्रविष्टियों की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है, जिससे बड़े पैमाने पर धन विदेश भेजा जा सका।

सर्राफा बाजार में तेजी का रुख, सोना और चांदी की बढ़ी कीमत

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज तेजी का रुख नजर आ रहा है। कीमत में तेजी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज प्रति 10 ग्राम 1,02,360 रुपये से लेकर 1,02,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, 22 कैरेट सोना आज 94,190 रुपये से लेकर 94,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में तेजी आने के कारण कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,24,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,02,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 94,340 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,02,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 94,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,02,410 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 94,240

रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,02,360 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 94,190 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,02,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 94,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,02,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 94,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 94,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,02,510 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 94,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव में तेजी का रुख नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 1,02,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 94,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

बाइकबॉट घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 394.42 करोड़ की संपत्तियां अटैच

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की स्पेशल टास्क फोर्स ने बाइकबॉट घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए), 2002 के तहत 394.42 करोड़ रुपए से अधिक की अचल और चल संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी ने जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, वे कमाख्या एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कमाख्या एजुकेशनल सोसायटी, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, अल्पाइन टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी, एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट और मीना आनंद के नाम पर पाई गईं। ईडी की जांच में सामने आया कि जीआईपीएल और इसके प्रमोटर संजय भाटी ने 'बाइकबॉट' नामक बाइक टैक्सी सेवा के नाम पर लोगों को निवेश का लालच दिया। दरअसल, कंपनी ने योजना बनाई थी कि कोई भी ग्राहक 1, 3, 5 या 7

बाइक्स में निवेश कर सकता है। इसके बाद, कंपनी उन बाइक्स को चलाकर निवेशक को मासिक किराया, ईएमआई, बोनस और रेफरल पर अतिरिक्त इंसेंटिव देगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फ्रेंचाइजी भी दी गई, लेकिन हकीकत यह थी कि अधिकांश शहरों में बाइक टैक्सी सेवा कभी शुरू ही नहीं हुई। ईडी की जांच से यह भी खुलासा हुआ कि निवेशकों से जुटाई गई रकम को संबंधित कंपनियों में डायवर्ट कर दिया गया और बाद में शैक्षिक ट्रस्ट, सोसायटी और व्यक्तियों के माध्यम से उपयोग किया गया। इस पैसे से मेरठ में कई अचल संपत्तियां खरीदी गईं और बैंकों से पहले से गिरवी रखी जमीनों को छुड़ाया गया। ईडी ने इस मामले में कुल 394.42 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया है। इसमें अचल संपत्तियां और गिरवी छुड़ाई गई जमीन शामिल हैं, जिनका मूल्य लगभग ?20.49 करोड़ है। इसके अलावा, अपराध के समय मूल्यांकन की गई संपत्तियों का मूल्य लगभग ?389.30 करोड़ आंका गया है। इसके साथ ही, 5.12 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट भी अटैच की गई हैं। इससे पहले भी ईडी ने तीन अस्थायी अटैचमेंट आदेशों (20 जुलाई 2020, 4 अक्टूबर 2021 और 10 मई 2024) के जरिए 220.78 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुकी है।

अमेरिकी टैरिफ के कारण शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, पूरे सप्ताह बना रहा बिकवाली का दबाव

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा भारत पर थोपे गए अतिरिक्त टैरिफ की वजह से बने दबाव के माहौल और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के कारण घरेलू शेयर बाजार लगातार दो सप्ताह की तेजी के बाद इस सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ। खत्म हुए कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स साप्ताहिक आधार पर 1,497.20 अंक यानी 1.84 प्रतिशत टूट कर 79,809.65 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी ने 443.25 अंक यानी 1.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,426.85 अंक के स्तर पर इस सप्ताह के कारोबार का अंत किया। सोमवार से शुक्रवार तक के कारोबारी सप्ताह में बीएसई का लार्जकैप इंडेक्स 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। इस इंडेक्स में शामिल एचडीएफसी ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी, आईडीबीआई बैंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंटर ग्लोब एविएशन, हुंडई मोटर इंडिया, आईसीसी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, वारी एनर्जीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर टॉप लूजर्स की सूची में शामिल हुए। इसी तरह बीएससी का मिडकैप इंडेक्स 25 से 29 अगस्त के कारोबारी सप्ताह के दौरान तीन प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इस इंडेक्स में शामिल पी बी फिनटेक, टाटा एलेक्सी, निप्पॉन लाइफ इंडिया ऐसेट मैनेजमेंट, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, बंधन बैंक, इमामी, क्रिसिल, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट और अजंता फार्मास्यूटिकल्स के शेयर टॉप लूजर्स की सूची में शामिल हुए। दूसरी ओर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, कन्साइ नैरोलैक पेंट्स, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डालमिया भारत के शेयर टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए।

मजबूत लिस्टिंग के बाद क्लासिक इलेक्ट्रोड्स के शेयरों पर लगा लोअर सर्किट

एजेंसी

नई दिल्ली। वेल्डिंग कंज्यूमबेल्स बनाने वाली कंपनी क्लासिक इलेक्ट्रोड्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में प्रीमियम एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। हालांकि निवेशकों की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि लिस्टिंग के बाद बिकवाली के दबाव की वजह से कंपनी के शेयर पर लोअर सर्किट लग गया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 87 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 14.94 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 100 रुपये के स्तर पर हुई। मजबूत लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर फिसल कर 95 रुपये के लोअर सर्किट लेवल

पर पहुंच गए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशक लोअर सर्किट लगने के बावजूद 9.91 प्रतिशत के फायदे में हैं। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स का 41.51 करोड़ रुपये का आईपीओ 22 से 26 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 179.97 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 84.88 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 356.75 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 158.44 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 47,71,200 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई मशीनरी और प्लांट खरीदने, पुराने कर्ज को कम करने, अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 1.49 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 2.08 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 12.30 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

अनोंदिता मेडिकेयर की स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री, मजबूत लिस्टिंग से निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा

एजेंसी

नई दिल्ली। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 145 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 90 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 275.50 रुपये के स्तर पर हुई। मजबूत लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयर की चाल में तेजी आ गई। सुबह 10:15 बजे तक का कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 288 रुपये के स्तेर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 98.62 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। अनोंदिता मेडिकेयर का 69.50 करोड़ रुपये का आईपीओ 22 से 26 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जोरदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 153.03 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 531.82 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 47.93 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नए इक्विपमेंट और मशीनरी की खरीदारी करने, अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 35 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 3.84 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 16.42 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

अपतटीय पवन ऊर्जा में निवेशक नहीं दिखा रहे रुचि

एजेंसी

नई दिल्ली। बुनियादी ढांचे की कमी और ज्यादा पारेषण लागत के कारण देश में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना उड़ान नहीं भर पा रही है। देश में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता इस साल 50 गीगा वाट को पार कर चुकी है और सरकार ने साल 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 गीगा वाट करने का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से औसतन हर साल 10 गीगा वाट की क्षमता जोड़नी होगी। पिछले तीन वित्त वर्षों के आंकड़े देखें तो 2022-23 में पवन ऊर्जा क्षमता 2.28 गीगा वाट, 2023-24 में 3.25 गीगा वाट और 2024-25 में 4.15 गीगा वाट बढ़ी थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1.64 गीगा वाट क्षमता जोड़ी गयी है और कुल स्थापित क्षमता 51.67 गीगा वाट हो गयी है। इस रफ्तार से साल 2030 तक 48 गीगा वाट का लक्ष्य मुश्किल लगता है।सरकार ने पवन ऊर्जा के विस्तार के लिए अपतटीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना बनायी है, लेकिन वह परवान चढ़ती नहीं दिख रही है। पहले चरण में सरकार ने कुल 10 मेगावाट की दो परियोजनाओं के लिए तैयारी की है। ये परियोजनायें गुजरात और तमिलनाडु में पांच-पांच गीगा वाट के संयंत्र स्थापित करने की हैं। दोनों राज्यों में 500-500 मेगा वाट के लिए सरकार ने वायेविलिटी गैप फंडिंग के जरिये नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया था।

औद्योगिक उड़ान : मोदी सरकार में रोजगार में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

एजेंसी

भोपाल। वर्ष 2014 में जब केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से लेकर 2025 तक देश की जनसंख्या घनत्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अधिक जनसंख्या का सीधा अर्थ है अधिक मानव संसाधन और ऐसे में हर हाथ को काम देना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना शुरू से ही हर सरकार के लिए कठिन कार्य रहा है, लेकिन पिछले वर्षों में केंद्र की योजनाओं और औद्योगिक नीतियों ने इस कठिनाई को अवसर में बदल दिया है। यही वजह है कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में देश न केवल मजबूती से आगे बढ़ रहा है बल्कि उद्योगों के जरिए पर्याप्त रोजगार भी सृजित कर रहा है। आज इन नौकरियों ने देश के करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना दिया है। इस दिशा में हाल ही में जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 के आंकड़े सरकार के इस दावे को मजबूती प्रदान करते दिखते हैं।

सर्वेक्षण का महत्व

दरअसल, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जिसमें भारत की औद्योगिक तस्वीर साफ दिखाई देती है। इसका मकसद उत्पादन, मूल्यवर्धन, रोजगार, पूंजी निर्माण और उद्योगों की संरचना में हो रहे बदलावों को दर्ज करना है। इस बार का फील्ड वर्क अक्टूबर 2024 से जून 2025 के बीच हुआ। रिपोर्ट राज्य और प्रमुख उद्योग स्तर पर तैयार की गई है और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है।

औद्योगिक विकास की रफ्तारः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हाल ही में एएसआई रिपोर्ट जारी की है। इसमें साफ दिखता है कि भारतीय उद्योग अब वैश्विक सुस्ती को पीछे छोड़ कर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में पिछले वर्ष की तुलना में 11.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कंपनियां न केवल उत्पादन कर रही हैं बल्कि अपने उत्पादों में वैल्यू एडिशन भी तेजी से बढ़ा रही हैं। यही नहीं, औद्योगिक उत्पादन में भी 5.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बताता है कि देश का विनिर्माण क्षेत्र रफ्तार पकड़ चुका है।

रोजगार सृजन की मजबूत तस्वीरः भारत जैसे विशाल देश के लिए रोजगार सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह एएसआई रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार में 5.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 1.8 करोड़ लोग उद्योगों से जुड़े थे, जबकि अब यह आंकड़ा 1.9 करोड़ से भी अधिक हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ एक वर्ष में ही लाखों लोगों को नए अवसर मिले।:पिछले एक दशक की तस्वीर और भी उत्साहजनक है। 2014-15 से लेकर 2023-24 तक, यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से अब तक, औद्योगिक क्षेत्र में करीब 57 लाख नई नौकरियां जुड़ी हैं। दरअसल, यह उपलब्धि साधारण नहीं है। जिस दौर में दुनिया के कई देशों में बेरोजगारी बड़ी चुनौती बनी हुई है, भारत ने उद्योगों को मजबूत कर रोजगार का एक नया परिदृश्य तैयार किया है।

पूंजी निवेश का उछालः एएसआई रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उद्योगों में निवेश का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। 2023-24 में कुल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 68 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 2022-23 के 61 लाख करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। यह वृद्धि बताती है कि उद्योगपति और कंपनियां न केवल भारत को भविष्य का बाज़ार मान रहे हैं बल्कि यहां अपनी पूंजी सुरक्षित और लाभकारी भी मानते हैं।

अब शरवरी वाघ

आलिया भट्ट की होगी भयंकर टक्कर! वॉर 2 छोड़िए, 'पठान-टाइगर' भी देखते रह जाएंगे!

ङ्क्रन्न का बहुत बड़ा दांव बुरी तरह से फेल हो गया. 400 करोड़ के बजट में बनी ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' भारत से अबतक 250 करोड़ भी नहीं कमा पाई है. वहीं दूसरी ओर खबरें आ रही हैं कि ङ्क्रन्न ने जूनियर एनटीआर के साथ स्टैंडअलोन फिल्म को रोक दिया है. अब असली टेंशन अगली फिल्म को लेकर है. इस यूनिवर्स की पहली फीमेल स्पाई फिल्म के लिए आलिया भट्ट और शरवरी वाघ को लिया गया है. दोनों अपनी फिल्म का काम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं. वहीं फिल्म की छोटी सी झलक 'वॉर 2' के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिली थी.

यूं तो 'अल्फा' में बॉबी देओल ही असली विलेन हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि वो आलिया भट्ट और शरवरी वाघ से लड़ते दिखेंगे. पर उससे पहले दोनों एक्ट्रेस, जिन्हें इस फिल्म की फीमेल स्पाई कहा जा रहा है क्यों भिड़ने वाली हैं ? हाल ही में एक न्यूज वेब साइट पर खबर छपी. जिससे पता लगा कि दोनों ने फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली है. इसी के साथ ही फिल्म के सबसे बड़े हाइलाइट वाले हिस्से को भी पूरा किया गया.

क्या आलिया भट्ट से भिड़ेंगी शरवरी ?

YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म हो और उस में कोई डांस नंबर न डाला जाए, यह तो एकदम पॉसिबल नहीं लगता. यही वजह है कि 'वॉर 2' के बाद अब Alpha में भी डांस नंबर देखने को मिलने वाला है. नई रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के बीच एक डांस फेस ऑफ करवाया गया है. फिल्म के इस गाने को आखिरी शेड्यूल में शूट किया गया है. सबसे खास बात यह है कि दोनों एक्ट्रेस के लिए अलग-अलग सिंगर्स गाना गा रहे हैं.

वहीं, पिक्चर का फाइनल कट 31 अगस्त यानी आज सौंप दिया जाएगा.यह भी बताते चलें कि पूरी फिल्म के लिए जो साउंड है, उसके डिजाइन पर अभी भी काम किया जा रहा है. वहीं, 'अल्फा' का बैकग्राउंड स्कोर भी अबतक तैयार नहीं किया गया है. जिस पर जल्द ही काम कंप्लीट हो जाएगा. साथ ही फिल्म में जो एक्शन सीन्स होने वाले हैं, उसमें भी काफी बदलाव किए गए हैं. बीते दिनों पता लगा था कि फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो होगा. वो कबीर बनकर दोनों की मदद करते दिखेंगे.

पहले भी डांस फेस ऑफ से मचाया धमाल

'वॉर 2' में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच एक फेस ऑफ रखा गया था. Janaab-e-Aali गाने को काफी पसंद किया गया है. वहीं इससे पहले 'एक था टाइगर' का Mashallah भी हिट रहा था. बात 'वॉर' के Jai Jai Shivshankar और Ghungroo की भी होनी चाहिए. साथ ही शाहरुख खान ने झूमे जो पठान ने भी खूब धमाल मचाया था. देखना होगा कि आलिया और शरवरी क्या नया करती दिखेंगी ?

मुझसे शादी करोगी...नेशनल टीवी पर सलमान के सामने मृदुल तिवारी ने किया प्यार का इजहार

'बिग बॉस' के पिछले कई सीजन में आपने जोड़ियां बनते देखा होगा. 19वें सीजन में भी कुछ ऐसा होता दिख रहा है. शो में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मृदुल तिवारी और पोलिश एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है. मृदुल ने तो 'बिग बॉस' के घर में नतालिया से प्यार का इजहार भी कर दिया. हालांकि, उन्होंने ऐसा सलमान के कहने पर किया.'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान नतालिया से पूछते हैं कि मृदुल आपको कैसा लगता है. इसपर नतालिया कहती हैं, मृदुल है मेरी जान.ये सुनकर मृदुल, सलमान और तमाम घरवाले मुस्कुराते नजर आते हैं.

यहां देखें मृदुल और नतालिया का वीडियो

उसके बाद सलमान दोनों को कहते हैं कि आओ दोनों डांस करके दिखाओ. उसके बाद दोनों सलमान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' के गाने 'दिल दियां गल्लां' गाने पर डांस करते हैं. दोनों को एक साथ देख सलमान और सभी घरवाले बेहद ही खुश नजर आते हैं. उसके बाद सलमान मृदुल को घुटने पर बैठने को कहते हैं. उसके बाद सलमान उन्हें पोलिश भाषा में नतालिया को कुछ कहने को कहते हैं. जैसा सलमान बोलते हैं वैसा ही मृदुल नतालिया से कहते हैं. उसके बाद सलमान नतालिया से कहते हैं कि बताओ मैंने मृदुल से क्या बुलवाया. इसपर नतालिया कहती हैं कि मृदुल ने कहा मुझसे शादी करोगी.

मृदुल तिवारी का रिएक्शन

ये सुनकर मृदुल कहते हैं, मजा बहुत आ रहा है. पहले दिन से ही शो में नतालिया और मृदुल के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. शो से जुड़े दोनों के वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. फैंस को भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही है.

बहरहाल, मृदुल एक फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन यानी 56 लाख फॉलोअर्स हैं. वहीं उनके यूट्यूब चैनल पर 19 मिलियन यानी 1 करोड़ 90 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. नतालिया पोलैंड की रहने वाली हैं. उन्होंने '365 डेज', 'चिकन करी लॉ' जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया है.

सिद्धार्थ-जान्हवी की 'परमसुंदरी' पर भारी पड़ी ये गुजराती फिल्म, 'कुली'-'वॉर 2' का भी बजाया बैंड!

अगस्त में भी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी. पर जिस बॉलीवुड फिल्म से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसका एक हफ्ते में ही दम निकल गया. वॉर 2 और कुली की आंधी तो नहीं चली, जिसके बाद परमसुंदरी ने थोड़ा बहुत कमाना चालू कर दिया है. इन सबसे हटकर एक गुजराती फिल्म ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है. जानिए कौन सी फिल्म है और कितने करोड़ कमाए.

अगस्त में रिलीज हुई दो फिल्मों से जैसी उम्मीद थी, वो वैसा कारोबार नहीं कर सकी. जहां ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' ङ्क्रन्न की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई. तो वहीं दूसरी ओर रजनीकांत की 'कुली' में एक ठीक-ठाक कहानी है. पर लोकेश कनगराज जैसी फिल्में बनाते हैं, उस हिसाब से बेस्ट तो नहीं है. अब उन दोनों ही फिल्मों के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की 'परमसुंदरी' रिलीज हो गई है. जिसने 2 दिन में ठीक कमाई कर ली है. लेकिन अगर ये गुजराती फिल्म न होती, तो सिद्धार्थ की फिल्म और अच्छा कमाई कर सकती थी. जानिए कैसे सबकुछ वश में कर लिया गया है.'परमसुंदरी' के अलावा गुजराती फिल्म 'वश लेवल 2' को भी काफी पसंद किया जा रहा है. पहली वाली फिल्म 'वश' से इस बार डर का लेवल कहीं ज्यादा है. अब क्योंकि वश के हिंदी रीमेक 'शैतान' को लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था. तो इस बार सीधा ये गुजराती फिल्म देखने लोग थिएटर पहुंच रहे हैं. जानिए किस फिल्म ने कितना काराबोर किया ?

सिद्धार्थ-जान्हवी की फिल्म की कमाई ?

सैकनिल्क की रिपोर्ट सामने आ गई है. 'परमसुंदरी' ने दूसरे दिन 9 करोड़ कमाए हैं. जो पहले दिन की तुलना में ज्यादा है. पर वीकेंड में और अच्छा कलेक्शन हो सकता था. क्योंकि अगर संडे को भी कमाई ऐसी ही रही, तो मामला गड़बड़ा सकता है. पहले दिन फिल्म ने 7.25 करोड़ का बिजनेस किया था. इसी के टोटल भारत से 16.25 करोड़ का कारोबार कर लिया गया है. हालांकि, 'परमसुंदरी' में सिद्धार्थ और जान्हवी कपूर की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है. खासकर सिद्धार्थ के नए अंदाज की काफी तारीफ की गई है.

'वश लेवल 2' को मिल रहा प्यार

जानकी भोदीवाला और हितेन कुमार की 'वश लेवल 2' को हिंदी ऑडियंस काफी प्यार दे रही है. इस बार फिल्म में डर का लेवल कई गुना ज्यादा है. खासकर जब स्कूल की लड़कियों को वश में कर लिया जाता है. जहां फिल्म ने पहले दिन भारत से 1.15 करोड़ छापे.

शाहरुख की अधूरी 'लव स्टोरी' अब प्रियंका चोपड़ा करेंगी पूरी! खेला बहुत बड़ा दांव

शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की फिल्मों ने फैन्स को खूब इम्प्रेस किया. दोनों की जोड़ी को भी काफी प्यार मिला है. यूं तो दोनों ही स्टार्स को लेकर कई किस्से वायरल हैं, पर अब वो अपनी-अपनी बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं. जहां बच्चों के करियर के साथ ही शाहरुख खान को 'किंग' पर काम करना है. वहीं दूसरी ओर प्रियंका चोपड़ा भी जल्द इंडियन सिनेमा में वापसी कर रही हैं. वो इस वक्त राजामौली की SSMB29 के शूट में बिजी हैं. इसी बीच शाहरुख खान की बंद पड़ी फिल्म की कहानी में प्रियंका ने क्या दांव खेला है.हाल ही में एक न्यूज वेब साइट पर प्रियंका के अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी सामने आई. जिसके मुताबिक, एक्ट्रेस ने अपने बैनर पर्पल पेबल पिक्चर्स के बैनर तले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. यह एक इंडियन-स्वीडिश प्रोजेक्ट है. बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वो 'द साइकिल ऑफ लव' नाम की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ गई हैं. लेकिन शाहरुख खान की फिल्म से इसका कैसा कनेक्शन है ?

प्रियंका की फिल्म का शाहरुख से कनेक्शन!

दरअसल प्रियंका चोपड़ा अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जिस प्रोजेक्ट से जुड़ी है, वो शाहरुख के चलते चर्चा में हैं. इस फिल्म का कनेक्शन लंबे समय से बंद पड़ी बॉलीवुड पिक्चर 'इजहार' से है. इस कहानी पर संजय लीला भंसाली 2013 में एक फीचर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे. जिसमें शाहरुख खान पीके महानंदिया की भूमिका निभा रहे थे. एक इंडियन, जिसके पास मुट्ठी भर पेंटब्रश और एक सैकंड हैंड रैले साइकिल थी. वहीं इसी के साथ प्रेमिका को ढूंढने एशिया और यूरोप की जर्नी पर निकल पड़ते हैं.इतना ही नहीं, वॉर्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर

संजय लीला भंसाली ने शाहरुख खान के साथ इस दूसरी फिल्म पर काम किया था. पहली बार 'देवदास' के लिए साथ आए थे. पर बाद में बिना वजह बताए फिल्म को चुपचाप बंद कर दिया गया. हालांकि, साल 2019 में यह प्रोजेक्ट फिर चर्चा में आया. जब पता लगा कि भंसाली ने 'इंशाअल्लाह' को बंद कर 'इजहार' पर काम करने का फैसला लिया है. हालांकि, ये अफवाहें गलत साबित हुईं.

न्यूज फ्लैश

देवरिया : आरपीएफ इंस्पेक्टर को किन्नरों ने दौड़ा कर पीटा, दो हिरासत में

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में सदर रेलवे स्टेशन परिसर में बीती रात रविवार को किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। इस दौरान किन्नरों ने इंस्पेक्टर की दौड़ा कर पिटाई कर दी। यह मारपीट यात्रियों से वसूली करने के चलते किन्नरों के एक गुट ने की है। मामले में आरोपितों के खिलाफ आरपीएफ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आरपीएफ अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बीती रात सदर रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद ने कुछ किन्नरों को यात्रियों से जबरन वसूली करते देखा। जबरन वसूली को उन्होंने रोकने की कोशिश की और किन्नरों को समझाने लगे। इससे किन्नर भड़क गए और कहासुनी करते हुए इंस्पेक्टर से अभद्रता करने लगे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि किन्नरों ने इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया।अचानक हमले के चलते इंस्पेक्टर किसी तरह अपनी जान बचाकर आरपीएफ चौकी की तरफ भागे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में शामिल किन्नरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सभी आरोपितों को पकड़ते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घायल इंस्पेक्टर को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है। किन्नरों की मारपीट के दौरान इंस्पेक्टर सादे कपड़ों में थे।
वहीं इस मामले में जीआरपी ने मुकदमा दर्ज करते हुए दो किन्नरों को हिरासत में लेते हुए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहे मारपीट करने वालों से पहचान करते हुए कार्रवाई में जुट गई है।

लखनऊ में ऑटो चालक की पड़ोसी ने चाकू मारकर की हत्या

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऑटो चालक की पड़ोसी ने सोमवार को चाकू मारकर हत्या कर दी। सूचना पाकर गोसाईगंज पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी। आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है।
थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मोहनलालगंज के गदियाना मोहल्ले में रहने वाला पवन कुमार (27) ऑटो चालक था। वह रोजाना की तरह ऑटो चलाने के लिए घर से निकला था। उसके साथ मोहल्ले का ही मोहित रावत भी था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उम्मेदखेड़ा पहुँचते ही मोहित और पवन में झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान उसने पवन की गर्दन पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। पवन मदद के लिए चिल्लाने लगा तो राहगीरों को आता देख आरोपित मोहित भागने लगा। भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। उधर, सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुँची तो देखा कि ऑटो चालक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस उससे अपराध के पीछे की वजह जानने के लिए पूछताछ कर रही है।

लखनऊ: विभूतिखंड थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी निलंबित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कमिश्नरेट पुलिस ने विभूतिखंड थाना प्रभारी और समिट बिल्डिंग चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। हसनगंज थाना प्रभारी अमर सिंह को विभूतिखंड का नया थाना प्रभारी बनाया गया है।

पायनियर कान्वेंट स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी 'खोज' ने दिखाया नवाचार का उजाला

दिव्य दिल्ली : पायनियर कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी "खोज" का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी ने पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़ते हुए डिजिटल तकनीक, स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक शिक्षण प्रणाली को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में छात्रों की सोच और प्रयासों को उजागर किया। छात्रों ने आयुर्वेद, वनस्पति विज्ञान, सिंधु घाटी सभ्यता, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नवाचार युक्त प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी में अ.1 द्वारा निर्मित 'रिस्को कार' विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जो पर्यावरण-हितैषी तकनीक की दिशा में भविष्य की सोच को दशार्ती है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित प्रोजेक्ट ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर संदीप, डी.ओ. तरुण बजाज, पूर्व काउंसलर सुरेश पहलवान, बॉलीवुड अभिनेता आशीष, दिवीज बजाज, मल्लिका बजाज, विभोर बजाज, वंशिका बजाज, एम.एन. तिवारी (विश्व जागृति मिशन), तथा फहअ के सदस्य राकेश, हेमंत और सुनील सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बच्चों की रचनात्मकता और प्रस्तुति ने अभिभावकों और मेहमानों को भावविभोर कर दिया। फ्रेंच क्लब द्वारा प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक प्रस्तुति ने भी सभी दर्शकों का मन मोह लिया और कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। विद्यालय की प्राचार्या डॉ. सीमा बजाज और उपप्राचार्या श्रीमती कमलेश कौर ने बच्चों के उत्साह और मेहनत की सराहना की तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रदर्शनी "खोज" न केवल छात्रों के ज्ञान और प्रतिभा को मंच प्रदान करने वाली साबित हुई, बल्कि समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी एक सराहनीय पहल रही।

ओएसिस स्किनकेयर एंड वेलनेस क्लिनिक का हुआ भव्य उद्घाटन समारोह

दिव्य दिल्ली : राजौरी गार्डन में ओएसिस स्किनकेयर एंड वेलनेस क्लिनिक का भव्य उद्घाटन समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन ज्ञान सिंह, डॉ. हंसराज शर्मा और योगेंद्र वत्स द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जानी-मानी फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी कायनात अरोड़ा ने शिरकत की। उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, गणमान्य अतिथि और उद्योग जगत के विशेषज्ञ उपस्थित रहे और क्लिनिक की अत्याधुनिक सुविधाओं व सेवाओं की सराहना की। ओएसिस स्किनकेयर एंड वेलनेस क्लिनिक को राजधानी दिल्ली में सौंदर्य और वेलनेस के क्षेत्र में एक नए युग की शुरूआत माना जा रहा है। अमेरिका और जर्मनी से आयातित नवीनतम लेजर मशीनों से सुसज्जित यह क्लिनिक विश्वस्तरीय गैर-आक्रामक और न्यूनतम आक्रामक उपचार प्रदान करता है। यहां स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, पीआरपी थेरेपी, लेजर थेरेपी, एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट्स, डर्मल फिलर्स, केमिकल पील्स और माइक्रोडर्माब्रेशन जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। अनुभवी विशेषज्ञों और आधुनिक तकनीक के संयोजन से हर ग्राहक को व्यक्तिगत देखभाल के साथ सर्वोत्तम परिणाम देने का प्रयास किया जाता है। ओएसिस क्लिनिक का उद्देश्य केवल सौंदर्य बढ़ाना ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक सुकून प्रदान करना भी है। राजधानी के प्रीमियम एस्थेटिक क्लिनिक के रूप में इस क्लिनिक की शुरूआत ने दिल्ली के वेलनेस उद्योग में नई पहचान और उच्च मानक स्थापित किए हैं।

लेगेसी ओपन लेडीज बनाम जेंटलमेन गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया

दिव्य दिल्ली : ग्रेटर नोएडा। जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित लेगेसी ओपन लेडीज बनाम जेंटलमेन गोल्फ टूर्नामेंट 2025 ने गोल्फ को एक अनोखे अंदाज में पेश किया। पहली बार महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने सीधे आमने-सामने मुकाबला किया, जिसने खेल को उत्सव का रूप दे दिया।
आलोक पस्कर की पहल और स्पॉटलाइट के राजीव वर्मा के संयोजन से आयोजित इस टूर्नामेंट में 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 50 महिलाएँ और 70 पुरुष गोल्फर शामिल रहे। कड़े मुकाबले के बाद राज सिंह (बेस्ट नेट), अब्बाका रावत (विमेन ग्रॉस), आन्या (विमेन नेट), आशीष कपूर (मेंस ग्रॉस) और डू यंग ली (मेंस नेट) विजेता बने। आयोजन में जेके टेक, अरमान रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और एचपी का विशेष सहयोग रहा, जबकि जेपी ग्रीन्स के ध्रुवपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा। आलोक पस्कर ने घोषणा की कि वे अगले पांच वर्षों तक इस टूर्नामेंट को प्रायोजित करेंगे और इसका अगला संस्करण 16 अक्टूबर 2026 को और बड़े स्तर पर होगा। लेगेसी ओपन 2025 ने परंपराएँ तोड़कर खेल में समावेशिता और समुदाय की नई मिसाल पेश की।

द्वारका स्थित पैसिफिक मॉल डी21 में "Rising Star 2.0" का ग्रैंड फिनाले आयोजित

दिव्य दिल्ली: दिल्ली के द्वारका स्थित पैसिफिक मॉल **डी21** में **"Rising Star 2.0"** का शानदार ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से आई प्रतिभाओं ने अपनी कला का जादू बिखेरा। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन डॉ. कीर्ति ढींगरा और आशु आहूजा ने किया, जबकि शो की डायरेक्टर रजनीत कौर रहीं। यह कार्यक्रम **"Ms India Bold & Beautiful"** संस्था के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ। कुल 88 प्रतिभागियों ने इस आयोजन में भाग लिया, जिन्हें उनकी आयु और प्रतिभा के आधार पर पर्ल, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड श्रेणियों में विभाजित किया गया था।
कार्यक्रम में सेलिब्रिटी जूरी के रूप में मुकेश बहेड़ मौजूद रहे, वहीं ग्रैंड जूरी में जसविंदर और ज्योति चौहान ने निर्णायक भूमिका निभाई। सभी जजों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शो में हिर्दयांश नारंग, प्रियांशु ब्योमकेश, आराध्या सिन्हा, रूद्र सिन्हा, मोनिका गुलाटी, अशनूर कौर और सैयांश ब्योमकेश जैसी प्रतिभाओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के मेकओवर पार्टनर **"Make U Glam Academy** रहे, जबकि **"Perfume Point"** और **4C's Diamonds"** गिफ्टिंग पार्टनर के रूप में जुड़े। फिनाले के दौरान आयोजकों द्वारा सभी जजों को अवॉर्ड और गिफ्ट हैम्पर्स देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कुछ विशिष्ट अतिथियों को भी विशेष पुरस्कारों से नवाजा गया। **"Rising Star 2.0"** ऐसा मंच बना, जिसने उन प्रतिभाशाली बच्चों को एक पहचान दिलाई, जिन्हें अब तक अपनी कला दिखाने का उचित अवसर नहीं मिल पाया था। यह आयोजन न केवल प्रतिभाओं को मंच देने का सफल प्रयास था, बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास और भविष्य को नई दिशा देने वाली प्रेरणादायक पहल भी सिद्ध हुई।

आर. जे. रेखा राष्ट्रीय स्त्री शक्ति सम्मान 2025 से सम्मानित

दिव्य दिल्ली: कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में गंतव्य संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्त्री शक्ति सम्मान समारोह में जानी-मानी टीवी और रेडियो पर्सनेलिटी आर. जे. रेखा को रेडियो एवं टीवी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्त्री शक्ति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देशभर से चयनित 62 प्रतिभाशाली महिलाओं को स्त्री शक्ति सम्मान और 15 पुरुषों को गंतव्य राष्ट्रीय गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। सम्मान समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र माननीय श्री सुनील शास्त्री, पूर्व मंत्री श्री मंगतराम सिंघल सहित कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। गणेश वंदना, दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आयोजन की अगुवाई गंतव्य संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार त्यागी, डॉ. अर्चना त्यागी और उनकी टीम ने की।

फेस्टा ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए व्यापारियों से मदद की अपील की

दिव्य दिल्ली : फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा और अध्यक्ष राकेश यादव ने पंजाब में बाढ़ से प्रभारित लोगों की मदद के लिए व्यापारियों से आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में व्यापारियों को एकजुट होकर पीड़ितों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। पम्मा और यादव ने कहा कि मदद आर्थिक, सामग्री या श्रम किसी भी रूप में की जा सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि जब भी देश पर आपदा आई है, चाहे वह गुजरात का भूकंप हो या कारगिल युद्ध, व्यापारी कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि बढ़-चढ़कर सहयोग किया। इस बार भी वही भावना दिखानी होगी। दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि पंजाब के कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं, वहां के पशु पानी में बह गए हैं और लोगों को भोजन से लेकर पशुओं के चारे तक की भारी किल्लत का सामना करना पड रहा है। इतना ही नहीं, साबुन, टूथब्रश, मच्छरदानी, तेल और महिलाओं के लिए आवश्यक पैड जैसी बुनियादी जरूरतों की भी भारी कमी है। ऐसे हालात में व्यापारी समाज को राहत पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

फतेहाबाद और रतिया में अवैध पिस्तौलों सहित दो युवक गिरफ्तार

फतेहाबाद। अपराध और अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हरियाणा की पुलिस ने सोमवार को फतेहाबाद व रतिया क्षेत्र से दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में सीआईए रतिया पुलिस ने जांडवाला मोड़, अयालकी के पास एक संदिग्ध युवक को दबोचकर उसके कब्जे से 315 बोर की अवैध पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। सीआईए रतिया प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक रिछपाल ने बताया कि हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित गश्त कर रही थी।

बीएचयू में आईआईटी और बिरला छात्रावास के छात्रों के बीच जमकर मारपीट

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में रविवार देर शाम बीएचयू आईआईटी और बिड़ला छात्रावास के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। बिरला हॉस्टल के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। मारपीट में तीन छात्र घायल हो गए। मारपीट और हंगामा की जानकारी पाते ही प्राक्टोरियल बोर्ड के अफसरों के साथ पुलिस अफसर भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। छात्रों के हंगामा के चलते परिसर में देर तक अफरा–तफरी का माहौल रहा। अफसरों ने समझा बुझा कर छात्रों को किसी तरह शांत कराया। इस दौरान छात्र बड़ी संख्या में जुटे रहे। पूरे कैंपस में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों को हॉस्टल में ही रहने की सलाह दी गई है। सूत्रों के अनुसार रात 11 बजे बैरियर से निकलने को लेकर छात्रों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल पिछले साल आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ परिसर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। आईआईटी बीएचयू के पास बैरियर लगाए गए हैं। रात 10 बजे के बाद किसी भी छात्र या बाहरी व्यक्ति को उन रास्तों से गुजरने की अनुमति नहीं होती। इस बैरियर को लेकर अन्य संकाय के छात्रों को परेशानी होती है। इसलिए वे इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। आईआईटी के छात्रों के अनुसार रात में वे बैरियर से निकलकर अपने परिसर की तरफ जा रहे थे, तभी बिरला चौराहे पर कुछ छात्रों ने उन्हें रोककर पूछा कि क्या वे आईआईटी से हैं। इसके बाद बहस होने लगी। इतने में एक छात्र को थप्पड़ मारा गया, जिसके बाद कहासुनी और मारपीट हो गई।

प्रशासन कर रहा योजनाबद्ध तरीके से काम: विश्राम कुमार मीणा

कुरुक्षेत्र : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जलभराव की स्थिति को समय से नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। पटवारी और ग्राम सचिव को 24 घंटे गांवों में ही रहते हुए ग्रामीणों और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। सभी गांवों में रात के समय ठीकरी पहरा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जिला में स्थिति नियंत्रण में है। जिलावासियों को पैनिक होने की जरुरत नहीं है। किसी भी जानकारी को कंट्रोल रूम नंबर 01744-221035 पर किसी भी समय पर दे सकते हैं। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हिमाचल व उत्तरी क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सुबह करीब 42 हजार क्यूसिक पानी का बहना दर्ज किया गया। झांसा में भी नदी की स्थिति हाई फ्लड लेवल पर चल रही है। उन्होंने कहा कि जिले के गांव गोमती, मलिकपुर, तंगोर, कठवा को दौरा कर स्थिति को जाना गया है। गांव कठवा में सडक पर कट लगाकर पानी को पार करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि गांवों में व्यवस्था के लिए अधिकारियों की टीम नियुक्त की गई है। फिलहाल जिला में स्थिति नियंत्रण में है, किसी भी नागरिक को पैनिक होने की जरुरत नहीं है। जिला में कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहा है। साथ ही अधिकारियों का व्हाटसअप ग्रुप बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि नागरिकों से आग्रह है कि वो बिना कारण घर से बाहर ना निकलें। जरुरी होने पर पानी की स्थिति का पता करने के बाद ही बाहर जाएं।

गाजियाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर किया प्रदर्शन, राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के सम्मान में अभद्र टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार की शाम को कांग्रेस के जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा के महानगर महामंत्री पप्पू पहलवान के नेतृत्व में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मेरठ रोड पर एकत्र हुए और वहां से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल ही जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। पप्पू पहलवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के प्रति जिस प्रकार अभद्र, अपमानजनक, अमानवीय और देशद्रोही भाषा का प्रयोग किया गया है, उसने सम्पूर्ण समाज को आहत और शर्मसार किया है। यह बयान केवल मातृझसम्मान का ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा का भी घोर अपमान है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321